● वर्ष-3
● अंक-52
रायपुर, रविवार
08 अक्टूबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› विदेश घूमने का है मन तो...

नए झंडे का अनावरण करेंगे एयरफोर्स चीफ

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास में आठ अक्टूबर की तारीख काफी अहम साबित होने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार, वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी आठ अक्टूबर को एयरफोर्स के नए फ्लैग का अनावरण करेंगे। इससे पहले भारतीय नौसेना का झंडा भी बदला जा चुका है।

ब्रिटिश सरकार के दौर में कैसा था वायुसेना का झंडा?

वायुसेना के अनुसार, इतिहास के पन्नों को पलटने पर रॉयल इंडियन एयर फोर्स (आरआईएएफ) की जानकारी मिलती है। उसके बाद वायुसेना के लोगो में ऊपरी हिस्से में अंग्रेजी हुकूमत की झलक मिलती थी। आजाद भारत के पहले इस्तेमाल होने वाले झंडे में बाएं कैंटन में यूनियन जैक (ब्रिटेन का झंडा) और फ्लाई साइड पर आरआईएएफ राउंडेल (लाल, सफेद और नीले रंग का इस्तेमाल) इस्तेमाल किया गया था।

आजादी के बाद बदला वायुसेना का झंडा

भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में कहा कि 1947 में ब्रिटिश सल्तनत के भारत छोड़ने और देश की स्वतंत्रता के बाद, भारतीय वायु सेना का झंडा बदला गया। यूनियन जैक को भारतीय तिरंगे के साथ मिलाकर वायुसेना का फ्लैग तैयार हुआ। शाही वायु सेना यानी रॉयल एयरफोर्स (आरएएफ) राउंडल्स को निचले दाएं कैंटन में दिखाया गया। इसके अलावा तिरंगे का इस्तेमाल भी किया गया।

झंडा बदलने के कारणों पर वायुसेना का बयान

वायुसेना का झंडा बदलने के मकसद के बारे में एयरफोर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया, भारतीय वायु सेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए अब एक नया ध्वज बनाया गया है।

मोटे अनाज वाले आटे पर पर शून्य प्रतिशत जीएसटी

जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक लिए गए बड़े निर्णय, गन्ना किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 70 प्रतिशत मोटे अनाज वाले आटे को अगर खुला बेचा जाए तो इसपर पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसे पैक करके बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने शीरा पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक आज दिल्ली में हुई। वित्त मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि जीएसटी परिषद ने आज ईएनए पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है। यदि राज्य इस पर कर लगाना चाहते हैं, तो उनका ऐसा करने के लिए स्वागत है। यदि राज्य इसे छोड़ना चाहते हैं, तो इस पर निर्णय लेने के लिए उनका स्वागत है। जीएसटी परिषद इस पर कर लगाने का निर्णय नहीं ले रही है, हालांकि कर लगाने का अधिकार यहीं है। इसलिए राज्यों के हित में, यदि मैं शब्द का उपयोग कर सकूं तो हमने वह अधिकार राज्यों को सौंप दिया है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण में से एक, जो मैं खुशी के भाव से कहना चाहतह हूं कि जीएसटी काउंसिल बाजरा वर्ष में भाग लेना चाहती थी और इसलिए बाजरा के प्रचार-प्रसार में जीएसटी की भूमिका उसमें नजर आती है।

पाउडर के रूप में बाजरा प्रवाह की खाद्य तैयारी जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70त्न बाजरा होता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि वे एचएस 1901 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए पाउडर के रूप में बाजरा को किसी अन्य आटे के साथ मिश्रित किया जा रहा है, जहां बाजरा की संरचना 70त्न है, हम कहते हैं कि यदि वे पहले से पैक किए गए और लेबल किए गए फॉर्म के अलावा किसी अन्य रूप में बेचे जाते हैं तो उन पर 0त्न जीएसटी लगेगा। इसलिए यदि वे खुले में बेचे जाते हैं तो 0त्न, और केवल 5त्न यदि पहले से पैक किए गए।

उन्होंने बताया कि जीएसटी 28त्न से घटाकर 5त्न कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा और इससे उनका बकाया तेजी से चुकाया जा सकेगा क्योंकि मिलों या किसी और के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। परिषद और हम सभी को लगता है कि इससे पशु आहार के निर्माण की लागत में भी कमी आएगी, जो एक बड़ा विकास होगा। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी द्वारा 52वीं जीएसटी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स नोटिस का मुद्दा उठाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गेमिंग खेलने पर दिल्ली के मंत्री ही थी। कैसिनो पर, यह गोवा के मंत्री थे। वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली के मंत्री की चिंता इस बात पर अधिक थी कि उन पर कर लगाने से एक उभरता हुआ उद्योग खत्म हो जाएगा, हमारे युवाओं को इस उद्योग की जरूरत है। और, फिर इन कंपनियों को गए नोटिस का मुद्दा भी उठा रहे हैं। हमने उसे सुना। दिल्ली के मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस निर्णय पर 2.5-3 वर्षों से चर्चा हो रही है और क्या परिषद में लिया गया निर्णय एक युवा और युवा उद्योग को प्रभावित करने वाला है, जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो यह दिल्ली के मंत्री द्वारा ली गई लाइन थी।

लाल किले पर की गई घोषणाओं को लेकर बैठक

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान की गई विभिन्न घोषणाओं के कार्यान्वयन की तैयारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रधान मंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पीएम मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्ग को घर के स्वामित्व के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने घरों के लिए सौर ऊर्जा का प्रावधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनके प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा बैठक में शामिल होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में से थे। उन्होंने इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालने के लिए एक प्रस्तुति दी। पीएमओ ने कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधान मंत्री ने गरीबों और मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। इस घोषणा के अनुरूप, प्रधान मंत्री ने इस घोषणा को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की। अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधान मंत्री ने घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना को क्रियान्वित करने की तैयारियों की समीक्षा की।

खिलाड़ियों को बधाई

एशियाई खेलों में भारत के सौ पदक पूरे होने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वह भारतीय दल का 10 अक्टूबर को स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हर अद्भुत प्रदर्शन ने इतिहास रचा और हमारा हृदय गर्व से भर दिया। मैं दस अक्टूबर को हमारे एशियाई खेलों के दल का स्वागत करूंगा और खिलाड़ियों से बात करूंगा।''

छग में भाजपा ने बनाया चुनावी मास्टरप्लान

नई दिल्ली। भाजपा के धुर विरोधी भी चुनावों को लेकर पार्टी के जज्बे को सलाम करते हैं। क्योंकि देश के किसी भी कोने में चुनाव क्यों ना हों, लेकिन बीजेपी पत्थर पर भी कमल खिलाने जैसी मेहनत करती है। बता दें कि इस साल के अंत तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है। जिसके लिए बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए दमदार रणनीति बनाई है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ज्यादा से ज्यादा लाभ बीजेपी चुनाव में हासिल करने के लिए कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जब चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, तो उसके बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में पांच चुनावी सभाएं कर सभी 90 सीटों के मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। बीजेपी की योजना के मुताबिक शुरूआती तौर पर पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ के सभी पांच संभागों में जनसभाएं आयोजित होंगी। वहीं जरूरत पड़ने पर पीएम मोदी की जनसभाओं की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है।

बता दें कि राज्य पांच संभागों - रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर में बंटा हुआ है। रायपुर संभाग के तहत राज्य के 5 जिले और 20 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं बिलासपुर संभाग में 8 जिले और 24 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा दुर्ग संभाग में 7 जिले 20 सीटें, सरगुजा संभाग में 6 जिले 14 सीटें और बस्तर संभाग में राज्य का 7 जिला और विधान सभा की 12 सीटें आती हैं।

हर संभाग में होगी पीएम की रैली

विधानसभा चुनावों की तारीखों की ऑफिशियल घोषणा के बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में जनसभा को संबोधित कर वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। ऐसे में बीजेपी पहले ही तय कर चुकी है सभी सीटों के प्रत्याशियों को मंच पर बुलाकर वोटरों से रूबरू होने के साथ बीजेपी के लिए वोट मांगेगे। वहीं पार्टी छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी पीएम की लोकप्रियता को ज्यादा से ज्यादा भुनाना चाहती हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अभियंता संघ के अधिकारी-कर्मचारियों ने मुलाकात कर राज्य पॉवर कंपनियों के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा पर धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल से चर्चा के दौरान अभियंता संघ के अध्यक्ष श्री राजेश पांडेय ने कहा कि इस ऐतिहासिक घोषणा से विद्युतकर्मी खुश हैं और अब उन्हें राज्य के अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को स्मृति चिन्ह भेंटकर आभार जताया।

प्रमुख समाचार

जातिगत जनगणना देश को बांटने का चुनावी खेल है:अनिल

नईदिल्ली। देश में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। विपक्षी दलों की ओर से जातिगत जनगणना कराने की मांग की जा रही है। बिहार में जातिगत जनगणना कराया भी जा चुका है। सोमवार को इसकी रिपोर्ट जारी की गई। जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा विपक्षी दलों के निशाने पर है। वहीं, भाजपा शासित हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जातिगत जनगणना देश को एकजुट करने के बजाय उसको अलग-अलग टुकड़ो में बांटने का एक उचित प्रयास है। 70 साल बाद हमें भारतीय होकर जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। जातिगत जनगणना की प्रमाणिकता क्या है? भाजपा नेता ने आगे कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के हाथ में रजिस्टर आ गया कि जिसको चाहे उस जाति में डाल दे। क्या जनगणना में आने के बाद ही लोगों को लाभ मिलेगा? ये सब चुनावी खेल है पहले भी मंडल आयोग हुआ था। दूसरी ओर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कई जगहों पर जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। ये काम मानवता के लिए हुआ है। सरकार के पास डाटा होना चाहिए। उसी हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी। हम कई बार मांग कर चुके हैं।

चतुर्वेदी ने राघव चड्ढा का बंगला आवंटन के बाद किया समर्थन

नईदिल्ली। दिल्ली कोर्ट के आदेश के बाद राज्यसभा सचिवालय द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का बंगला आवंटन रद्द किए जाने के बाद शिवसेना (यूबीटी) उनके समर्थन में आ गई है। अब, भाजपा पर %प्रतिशोधात्मक रवैया% अपनाने का आरोप लगाते हुए, उद्धव सेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि बहुत से लोगों को समय से पहले आवंटन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों को ऐसे घर पाने का सौभाग्य मिला है जो उनकी श्रेणी में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो पता चलता है कि बहुत से लोग टर्म अलॉटमेंट से बाहर हो जाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे मकान मिल जाते हैं जो उनकी श्रेणी में नहीं होते। एक व्यक्ति को निशाना बनाना सत्तारूढ़ दल के प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है। इससे पहले, आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने बंगले का आवंटन रद्द करने के कदम की निंदा करते हुए इसे मनमाना और अभूतपूर्व बताया। चड्ढा ने आरोप लगाया कि रद्दीकरण भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।

इमरान मसूद की हुई कांग्रेस में वापसी

नईदिल्ली। पूर्व विधायक इमरान मसूद शनिवार को दिल्ली स्थित मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल हो गए और कहा कि जल्द ही सहारनपुर में पार्टी की एक बड़ी जनसभा बुलाई जाएगी। इस मौके पर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और यूपी के अध्यक्ष अजय राय मौजूद थे। वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला मसूद का कांग्रेस में स्वागत करते हुए कहा कि यह उनकी घर वापसी है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मसूद ने कहा कि वह कांग्रेस के सिपाही थे, लेकिन लगभग डेढ़ साल तक पार्टी से दूर रहे, लेकिन अब घर लौट आए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सराहना करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में बदलाव का युग शुरू हुआ है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलने की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी करेगी। पार्टी में वापसी पर मसूद ने इसे गर्व की बात बताया। अब जो भी आगामी कार्यक्रम होंगे वह पार्टी की नीति के अनुसार होंगे। जल्द से जल्द सहारनपुर में पार्टी के बैनर तले एक बड़ी रैली आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा।

बंगाल को मनरेगा राशि से वंचित नहीं किया: निरंजन

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल को कभी भी मनरेगा राशि से वंचित नहीं किया है और पिछले नौ वर्षों के आंकड़े यह साबित करते हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के जिलों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना कोष के उपयोग में विसंगतियां हैं। मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के इन आरोपों को खारिज किया कि उन्होंने मनरेगा के बकाया के संबंध में बातचीत के लिए नयी दिल्ली में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। ज्योति ने कहा, ''मैं उनसे मिलना चाहती थी और उनका लगभग ढाई घंटे तक इंतजार किया। लेकिन वे अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या को लेकर अड़े रहे।'' ज्योति ने दावा किया, ''वे अब झूठे आरोप लगा रहे हैं कि मैं पिछले दरवाजे से भाग गई। टीएमसी झूठ फैला रही है। वे मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, वे सिर्फ नाटक करना चाहते थे।''

इजरायल पर हमास का हमला, भारतीय एडवाइजरी जारी

नईदिल्ली। इजरायल और हमास के मध्य चल रहे युद्ध के बीच विदेश मंत्रालय भारतीयों से अनावश्यक आवाजाही से बचने और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहने का आग्रह किया है। एक सलाह में विदेश मंत्रालय ने कहा कि इज़राइल में सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इज़राइल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इज़राइल में सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सतर्क रहें, स्थानीय अधिकारियों द्वारा सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। सेना के प्रवक्ता रिचर्ड हेचट ने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवादी पैराग्लाइडर, समुद्र और जमीन के जरिए इजरायल में घुस आए। इससे पहले, हमास के गुर्गों द्वारा इज़राइल में सैकड़ों रॉकेट दागे गए थे। अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देश युद्ध में है और वे इसे जीतेंगे। इस बीच, इजरायली रक्षा मंत्री ने हमले की साजिश रचने वाले हमास को चेतावनी दी कि उसने इजरायल पर युद्ध की घोषणा करके गंभीर गलती की है। हमास द्वारा कई इजराइलियों के मारे जाने या उन्हें बंदी बना लिए जाने की खबर है।

चुनावी रणनीति

125 सीटों पर मोदी को रोकने का प्लान तैयार, संघ स्टाइल में काम करेंगे कार्यकर्ता

अमित शर्मा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1.0 बहुत सफल रही थी। कहा जाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के पीछे इस राज्य के नेताओं की कठिन मेहनत के साथ-साथ इस यात्रा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। अब उस यात्रा से निकले सकारात्मक परिणामों के सहारे लोकसभा की 125 सीटों पर भाजपा को रोकने का प्लान तैयार किया गया है। विपक्ष को उम्मीद है कि यदि वह भाजपा को उसकी वर्तमान सीट क्षमता में 100 सीटों की कमी कर सके, तो केंद्र में सरकार बनाने की संभावनाएं बन सकती हैं।

दरअसल, भारत जोड़ो यात्रा 1.0 को पूरी तरह गैर राजनीतिक रखा गया था। कांग्रेस ने इस यात्रा का नेतृत्व अवश्य किया था, लेकिन इसे किसी दल विशेष की यात्रा के तौर पर प्रचारित नहीं किया गया था। इसी का परिणाम हुआ कि इस यात्रा को डीएमके और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) जैसे दलों का साथ मिला। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस यात्रा की सफलता में सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का था, जो किसी दल विशेष से नहीं जुड़े थे। विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े ये लोग अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं और लोगों के बीच बेहतर पकड़ रखते हैं। एक अर्थ में लोग उनकी बातों को राजनेताओं से ज्यादा भरोसे के साथ सुनते और मानते हैं। अब इन्हीं लोगों को साथ लेकर देश की 125 अलग-अलग लोकसभाओं में लोगों को केंद्र सरकार की कार्यशैली से अवगत कराकर उन्हें विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा जाएगा।

कहां से कितनी सीटें

योजना से जुड़े एक कार्यकर्ता ने अमर उजाला को बताया कि इन 125 सीटों की पहचान उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के विभिन्न राज्यों से की गई है। जिन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने विपक्षी दलों से बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल की है, उन पर लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। इन राज्यों में दक्षिण की कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम के गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र और उत्तर भारत के यूपी-बिहार और पश्चिम बंगाल तक की सीटें शामिल हैं।

125 सीटों के चयन में लोकसभा सीटों की आबादी की विवेचना को सबसे ज्यादा प्रमुख आधार बनाया गया है। टीम के कोर सदस्यों का मानना है कि जिन लोकसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय, दलितों और पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पर लोगों को सरकार के उन कार्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह सरकार के कार्यों के कारण उनके अधिकारों में कटौती हो रही है। इस तरह लोगों को अपने साथ जोड़कर सरकार की राह में मुश्किल खड़ी की जाएगी।

होगा प्रशिक्षण

इस पूरी योजना को अमल में लाने में सबसे बड़ा रोल सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव निभा रहे हैं। वे भारत जोड़ो यात्रा 1.0 के सूत्रधारों में गिने जाते हैं। इस बार इन 125 सीटों पर भाजपा को हराने की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर डाली गई है। दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में हुई एक बैठक के बाद योगेंद्र यादव ने बताया था कि इन 125 लोकसभा सीटों में हर एक सीट पर एक हजार विशेष कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी, जो अगले छह महीने अपनी-अपनी लोकसभाओं में रहकर प्रचार-प्रसार करने का काम करेंगे। वे लोगों को जागरूक कर भाजपा के विरुद्ध वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे।

इन सभी कार्यकर्ताओं को अपना कार्य शुरू करने के पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उन्हें आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों के बीच रहकर उनसे मिलजुलकर अपनी बात रखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह कार्य ठीक उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने स्वयं सेवकों को तैयार कर विभिन्न क्षेत्रों में भेजकर सेवा कार्य करवाता है। अब इन कार्यकर्ताओं के सहारे भाजपा को रोक पाने की रणनीति कितनी सफल होती है, यह देखने वाली बात होगी।

यहां हो चुका है ये प्रयोग

लोकसभा चुनावों के स्तर पर यह प्रयोग पहली बार किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है।

जनकपुर ग्राम पंचायत को मिला नगर पंचायत का दर्जा, ग्रामवासियों ने सीएम को दिया धन्यवाद

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जनकपुर को नगर पंचायत बनाने की मांग आखिरकार पूरी हुई। छत्तीसगढ़ राजपत्र में जनकपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने की अधिसूचना जारी हुई। विकासखंड के सभी कार्यालय जनकपुर में होने की वजह से इस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की मांग की जा रही थी। जब सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के दौरान जिले के बहरासी में पहुंचे थे तो जनकपुर वासियों ने उनके सामने नगर पंचायत की मांग की थी।जिसके बाद सीएम भूपेश ने जनकपुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की।सीएम भूपेश की घोषणा के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब जनकपुर को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी हुई।

आपको बता दें नगर पंचायत जनकपुर में ग्राम पंचायत जनकपुर क्षेत्र को ही शामिल किया गया है। जनकपुर में एसडीएम कार्यालय से लेकर पुलिस थाना, जनपद पंचायत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, महाविद्यालय के अलावा कई शासकीय कार्यालय संचालित हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के समय से जनकपुर को नगर पंचायत बनाने की मांग होती रही है।लेकिन कांग्रेस शासन में जनकपुर को नगर पंचायत बनाया गया।

अंकुर सिंह, उपसरपंच ने कहा ग्राम पंचायत जनकपुर को नगर पंचायत बनाने की बहुत पुरानी मांग थी। जो 2009 से चली आ रही थी। लेकिन पिछली सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार में बरसों पुरानी मांग पूरी हुई। इस मांग के पूरे होने पर स्थानीय विधायक गुलाब कमरो ने सीएम भूपेश का आभार जताया।साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बेहद खुश हैं।

व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा यह ग्राम पंचायत अब नगर पंचायत बन चुका है। मेरा मानना है कि नगर पंचायत बनने के बाद अब गांव का विकास एक व्यवस्थित तरीके से विकास हो पाएगा। इतनी पुरानी मांग जो आज पूरी हुई है। इस पर हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं।

वहीं क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो ने जनता की बरसों पुरानी मांग पूरी होने पर प्रदेश के सीएम को धन्यवाद कहा है।गुलाब कमरो ने कहा कि सीएम भूपेश के इस फैसले से जनकपुर का विकास होगा।साथ ही साथ जल्द ही नगर पंचायत में सीएमओ की पदस्थापना करवा दिया जाएगा।

भेंट मुलाकात के दौरान हुई थी घोषणा

आपको बता दें कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश का जून महीने में भरतपुर में आगमन हुआ था। सीएम के सामने जनकपुर वासियों ने बढ़ती ग्राम पंचायत की जनसंख्या और पंचायत में फंड की कमी बताकर उनसे नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग की थी।सीएम भूपेश ने ग्रामीणों की परेशानी को समझते हुए आखिरकार बरसों पुरानी मांग को पूरा कर दिया।

चुनाव से पहले मंत्री अकबर ने करोंड़ों के निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

कबीरधाम। मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज शनिवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास के लिए एक करोड़ 28 लाख चार हजार रुपये की लागत से 16 विभिन्न निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया।

भूमिपूजन कार्यों में नवीन प्राथमिक शाला भवन, सामुदायिक भवन निर्माण, प्राथमिक शाला भवन निर्माण, बाउन्ड्रीवाल निर्माण, पचरी निर्माण, सांस्कृतिक मंच निर्माण, और मंगल भवन निर्माण कार्य शामिल है। मंत्री अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। गांव-गांव में लोकार्पण और भूमिपूजन के साथ छोटे-बड़े कार्यों के माध्यम से आमनागरिकों को सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जिले के विकास को प्राथमिकता में रखते हुए निर्माण कार्य कराए। उन्होंने कहा कि जिले के दूरस्थ अंचलों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य की दिशा में काम करते हुए अनेक परिवर्तन लाएं हैं। आज एक करोड़ 28 लाख चार हजार रुपये की लागत से 16 विभिन्न निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया गया है, इससे कबीरधाम जिले को एक नया आयाम मिलेगा।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए दपूमरे में नई तकनीक के समावेश के साथ डिजिटल पहल

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर यात्री सुविधाएं तथा सुरक्षा के साथ बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुरक्षा व संरक्षा तथा ट्रेनों में अपराध की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर ट्रेनों के कोच में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे का प्रावधान किया जा रहा है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 110 एलएचबी कोच, 72 ईएमयू के कोच तथा 8 डेमू कोच में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे गए है। इससे यात्रियों का सफर सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव के साथ सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होगा। ट्रेनों में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर इन कैमरों की मदद से डाटा को डाउनलोड करके उनका विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत यात्री ट्रेनों में बिलासपुर-नागपुर-बिलासपुर, वंदे भारत एक्सप्रेस, दुर्ग-निज़ामुद्दीन-दुर्ग, हमसफर एक्स्प्रेस के 22 कोच, कोरबा-अमृतसर-कोरबा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के 38 कोच, बिलासपुर-भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस के 13 कोच, बिलासपुर-पुणे व बिलासपुर-चेन्नई एक्सप्रेस के 06 कोच, बिलासपुर-पटना व बिलासपुर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 4 कोच, दुर्ग-निज़ामुद्दीन, संपर्कक्रांति व दुर्ग-जम्मूतवी एक्सप्रेस के 16 कोच सहित 11 स्पेयर कोच शामिल है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चलने वाली बल्लारशाह-गोंदिया मेमु के 12+12 कोच, चांदाफ़ोर्ट-गोंदिया मेमु के 12 कोच, गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमु के 12 कोच, झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमु के 12 कोच, केवटी-रायपुर डेमू के 8 कोच सहित 12 स्पेयर कोचों में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाए जा चुके है।

ट्रेनों में कोच के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 26 स्टेशनों के प्लेटफार्म व स्टेशन परिसरों में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाए गए है। इन कैमरों की मदद से आपराधिक एवं संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के साथ स्टेशनों पर यात्रियों के छूटे हुए सामानों की बरामदगी में भी सहायता मिल रही है। इसके अतिरिक्त संदिग्धों एवं अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा विवाद सुलझाने में कैमरे के फुटेज साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाये जा रहे है।

पुलिस की नौकरी छोड़ने की शर्त पर अपहृत जवान को नक्सलियों ने किया रिहा

बीजापुर। नक्सलियों ने बस्तर फाइटर के अपहृत जवान शंकर कुडियम को रिहा कर दिया है। नक्सलियों के जनअदालत में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के सामने शुक्रवार रात्रि 08 बजे पुलिस की नौकरी छोडने की शर्त पर रिहा कर दिया है। अपहृत जवान शंकर ने बताया कि वह अपने मित्र को लेने ग्राम उसपरी गया था, इस दौरान गांव के बाहर नक्सलियों कि मौजूदगी थी। नक्सलियों को जब जानकारी मिली कि बस्तर फाइटर का एक जवान गांव में घूम रहा हैं तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और लगातार उससे पूछताछ की जाती रही है। अपहृत जवान शंकर बताता है कि दिन में उसे किसी घर में रखा जाता था और उसे वहां भोजन पानी भी नियमित रूप से दिया जाता था। जब भी नक्सली कहीं आते जाते थे तो उसे भी साथ ले जाते थे। इस दौरान अलग - अलग नक्सलियों के साथ वह रहता था, लेकिन न तो उससे मारपीट की गई और न ही प्रताडना दी गई।

नक्सलियों के डीवीसी सदस्य सुखलाल ने जनअदालत के दौरान लोगों को बताया कि शंकर पुलिस का जवान था इसलिए ग्रामीणों ने उसे मार डालने कहा था, लेकिन समाज और परिजनों की अपील के कारण एक बार फिर उससे पूछताछ की और फिर समाज और परिजनों से पूछ-ताछ के बाद लोगों से चर्चा कर पूर्व के निर्णय पर पुनर्विचार

करते हुए शंकर कुडियम को कुछ शर्तों पर छोडने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनिय है कि अपहृत जवान शंकर बीजापुर के एरमनार गांव का आदिवासी युवक है, जो कुछ वर्ष पहले ही पुलिस बल में भर्ती हुआ था। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने जनअदालत लगाई थी, वे भी आदिवासी थे, पर नक्सलियों के साथ खड़े हैं। नक्सलवाद से बस्तर को क्या मिला है, यह दृश्य बता रहा था, क्योंकि एक पक्ष के साथ खड़े आदिवासी, दूसरे पक्ष के आदिवासी को जान से मारने उतारु हैं। इस जनअदालत में शंकर की ओर से पैरवी करने कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार वहां पहुंचे थे, जो उसे सुरक्षित ले जाने आए हुए थे, पर अंतिम निर्णय यहां नक्सलियों को ही सुनाना था।

एक नक्सली ने आरोप पढ़ा कि सुरक्षा बल ग्रामीणों पर अत्याचार करते हैं और शंकर भी उन्हीं में से एक है इसलिए उसे मौत की सजा देनी चाहिए। शंकर ने अपना पक्ष रखा कि वह परिवार के लालन-पोषण के लिए सुरक्षा बल में नियुक्त हुआ है। अनुनय-विनय के बाद शंकर ने कहा कि वह अब सुरक्षा बल की नौकरी छोड़कर गांव लौट जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारों ने भी शंकर को छोडने की नक्सलियों से अपील की। आखिरकार नक्सलियों ने निर्णय शंकर के पक्ष में सुनाया गया और उसे छोड़ दिया गया। एक सप्ताह तक नक्सलियों की कैद में बिताने के बाद अब शंकर को छोड़ दिया गया।

शंकर कुडियम को नक्सलियों की माड़ डिविजन ने 29 सितंबर को उसपरी घाट से अगवा कर लिया था, जहां वह अपने परिचित को छोडने गया हुआ था। गुरुवार को माड़ डिविजन कमेटी की सचिव अनिता मंडावी ने पर्चा जारी कर इसकी सूचना देते हुए जनअदालत लगाने की बात कही थी। एसपी बीजापुर आंजनेय वार्ष्णेय ने भी परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपील पर नक्सलियों से उसे रिहा करने की अपेक्षा की थी।

कोरबा में किंग कोबरा के संरक्षण के लिए बड़ी पहल

कोरबा। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला मध्य भारत में किंग कोबरा का एक मात्र घर है। यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सर्प प्रजाति है जो 18 फीट तक होता हैं। दो साल पहले इसके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से पहल की थी जिससे राज्य में पहली बार किंग कोबरा एवं इसके रहवास के बारे में विस्तृत जानकारियां पता चली।

कोरबा के अलग-अलग क्षेत्र से किंग कोबरा रिपोर्ट किए गए इसके साथ ही कई जगह इनके केचुली एवं घोसलों का पता चला जिससे इस बात की पुष्टि हुई की किंग कोबरा प्राय कोरबा जिले के अलग-अलग रहवास में पाया जा रहा है। इस खास प्रजाति के सर्प को और बारीकी से जानने एवं इनके रहवास का सर्वेक्षण करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई। इस निविदा का उद्देश्य स्थानीय लोगों को जागरूक करना और उनके माध्यम से इस दुर्लभ सरीसृप का संरक्षण करना और कोरबा जिले में बेहतर सर्पदंश प्रबंधन करना आदि शामिल है। निविदा में कुल तीन संस्थाओं ने भाग लिया जो राज्य की स्थानीय संस्थाएं थी।

टेक्निकल बिड, प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल बेड के उपरांत किंग कोबरा के निविदा हेतु नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी रायपुर का चयन किया गया। यह संस्था अगले एक साल कोरबा और उसके आसपास के वनों में इस दुर्लभ सरीसृप और साथ ही साथ अन्य सरीसृपों पर अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट वन विभाग को देगी। इस अध्ययन में किंग कोबरा से जुड़े कई सवाल जैसे क्यों यह जीव सिर्फ कोरबा में मिल रहा, इनकी संख्या घट रही या बढ़ रही, इनके संख्या को कोई समस्याएं तो नही आदि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस अध्ययन में मिलेंगे। स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए कैसे मानव वन्यजीव संघर्ष की स्तिथि में कार्य किया जाए, बच्चों में जागरूकता लाना, सर्प दंश के पीड़ितों को बेहतर प्रबंधन करना आदि शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 2022-23 तक 37 हजार 820 परिवार का बना मकान

सारंगढ़ बिलाईगढ़। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में बेघर गरीब लोगों को पक्का घर बनवाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपए हितग्राही परिवार को डीबीटी माध्यम से प्रदान कर रही है। इसमें केन्द्र सरकार के 72 हजार और छत्तीसगढ़ सरकार के 48 हजार अंशदान से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हितग्राही का मकान बनता है। इसमें दोनों सरकारों का अंशदान अनुपात केन्द्र 60 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ राज्य का 40 प्रतिशत राशि शामिल है। इसमें अनुपात 60:40 होता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले अंतर्गत 2016-17 से 2022-23 तक में बरमकेला ब्लॉक में 13 हजार 554 लक्ष्य था, जिसमें 10 हजार 710 आवास पूर्ण हो गया है। बिलाईगढ़ ब्लॉक में 14 हजार 297 आवास लक्ष्य था, जिसमें 10 हजार 848 आवास पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार सारंगढ़ ब्लॉक में 19 हजार 945 आवास लक्ष्य था, जिसमें 16 हजार 262 आवास पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार कुल लक्ष्य आवास 47 हजार 796 था, जिसमें 37 हजार 820 आवास-मकान पूर्ण हो चुका है।

20 अक्टूबर तक होगा छात्रवृत्ति हेतु पंजीयन

कोरिया। शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार राज्य व केन्द्रीय छात्रवृत्ति हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में 27 सितंबर 2023 से पंजीयन के लिए उपलब्ध कराया गया है। केन्द्रीय छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक सभी प्रमाण पत्र सीधे जारीकर्ता संस्था से सत्यापित किये जायेंगे। केन्द्रीय छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक कौई भी प्रमाण पत्र अपललोड किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। नये प्रावधान अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक पात्रताधारी सभी विद्यार्थी को स्वयं पोर्टल पर पंजीयन किया जाना है, जिनका सत्यापन शाला व जिला स्तर पर किया जावेगा। पोर्टल से संबंधित अन्य प्रमुख निर्देश के तहत राज्य/केन्द्रीय छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों का आधार से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पोर्टल पर स्वयं पंजीयन करना होगा। आवश्यक प्रमाण पत्र यदि ऑनलाईन बना हो तो सीधे विद्यार्थी के स्तर से ही अपलोड किया जा सकेगा। यदि ऑनलाईन प्रमाण पत्र न हो तो प्रमाण पत्र शाला में जमा किये जायेगें।

अवैध निर्माण प्रकरणों में 81 को अनुमति प्रदान की गई

गरियाबंद। कलेक्टर आकाश छिकारा ने विगत दिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण हेतु राजस्व, नगर पालिका एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की बैठक ली। समिति ने अनुमति के अतिरिक्त तथा बिना अनुमति के अवैध निर्माण प्रकरणों के 81 प्रकरणों को वैध किया। जिनमें गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र के 58 प्रकरण, नगर पंचायत राजिम के 16 प्रकारण, नगर पंचायत फिंगेश्वर के 2 प्रकरण, नगर पंचायत छुरा के 1 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 4 प्रकरण शामिल है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत जिले के नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था।

चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता कमर कस लें : अन्नपूर्णा यादव

कांकेर। भारत सरकार की केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री व झारखंड के कोडरमा से लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी यादव ने शनिवार को भाजपा कार्यालय कमल सदन कांकेर में कांकेर विधानसभा के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की चुनावी बैठक ली। अन्नपूर्णा देवी यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे चुनाव में आप लोगों के सहयोग के लिए भेजा गया है। आगामी एक-दो दिनों में चुनाव आचार संहिता लग जायेगी। आचार संहिता से पहले हम जितना ज्यादा प्रचार कार्यक्रम हो सके संपन्न कर लें क्योंकि उसके बाद चुनाव आयोग के नियमानुसार ही बैठकें, सभा कर पायेंगे। यादव ने आगे कहा कि बूथ के लोगों तक भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे है। केन्द्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। पिछले 15 वर्षो में भाजपा के शासनकाल में जो भी विकास के कार्य छत्तीसगढ़ में हुए है उनका प्रचार करें। संगठन की सभी कमेटियों को सक्रिय कर चुनाव कार्य में लगायें।

बस-कार की आमने सामने की भीषण दुर्घटना

कोंडागांव। केशकाल थाना क्षेत्र अंर्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ग्राम खालेमुरवेंड में शुक्रवार-शनिवार दरम्यानी रात लगभग 2 बजे बेकाबू नरेश ट्रेवल्स की बस ने विपरीत दिशा से आ रही महिंद्रा एक्सयूवी कार को जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक कृष्णा गर्ग, निवासी महाराष्ट्र की मौके पर ही मौत हो गई है, बस-कार बुरी तरह से छतिग्रस्त होने के कारण कार चालक घण्टो तक कार में ही फंसा रहा। भीषण दुर्घटना की सूचना पर केशकाल एसडीएम, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी आनंद सोनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घण्टों मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। केशकाल थाना प्रभारी आनंद सोनी ने बताया कि बस-कार की भीषण टक्कर होने के कारण चालक कार के भीतर ही बुरी तरह से दब गया था। सूचना पर हमारी टीम ने तत्काल मौके पर पंहुचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए केशकाल अस्पताल भेजा गया है। आरोपी बस चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

मिलेट्स को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए हैं अनेक निर्णय

- स्व सहायता समूह की महिलाएं उन्नत कोदो प्रसंस्करण, लाख उत्पादन को समझने मध्यप्रदेश रवाना

कोरिया। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार मिलेट्स मिशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। आदिवासी अंचल के मुख्य आय लघु वनोपज, तेंदूपत्ता की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, वहीं लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। कल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। श्री बघेल ने खरीफ 2023 हेतु कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3350 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो तथा कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। राज्य सरकार द्वारा कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। इसलिए छत्तीसगढ़ के मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा

कोदो- कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कोदो का समर्थन मूल्य जो वर्ष 2022-23 में 3000 प्रति क्विंटल था जिसे खरीफ 2023 हेतु बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का समर्थन मूल्य जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल था उसे बढ़ाकर 3350 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज शाम कोदो-कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो एवं कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3200 रूपए प्रति क्विंटल और कुटकी का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3350 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है। रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रूपए प्रति क्विंटल के अनुसार उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन अवधि का निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। कोदो-कुटकी एवं रागी का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाएगा। इसका लाभ जिले के किसानों को भी मिलेगा। जिले के कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के तहत स्व सहायता समूहों की 50 महिला सदस्यों को मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में कोदो प्रसंस्करण, लाख उत्पादन आदि के आधुनिक व उन्नत कृषि, उत्पादन, प्रसंस्करण को सीखने, समझने के लिए रवाना हुए।

संपत-सौरभ को टिकट न देने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन

रायगढ़। भारतीय जनता पार्टी की संभावित सूची जारी होने के बाद से गद्रे स्मृति भवन (भाजपा कार्यालय) में लगातार कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिख रहे है। कड़ी में शनिवार को बसना और अकलतरा से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया उनकी मांग थी कि बसना से संपत अग्रवाल और अकलतरा के मौजूदा विधायक सौरभ सिंह को किसी भी दशा में टिकट न दिया जाए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बसना से संपत अग्रवाल की टिकट तय होने की खबर आने के बाद से पूरे क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं और इसी बात की नाराजगी जताते सैकड़ों की संख्या में नाराज कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे और पदाधिकारियों से मिलकर संपत अग्रवाल के नाम पर आपत्ति जताई और साफ तौर पर कहा कि संपत किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। इसी तरह अकलतरा से भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। कार्यकर्ता मौजूदा विधायक सौरभ सिंह को किसी भी दशा में टिकट नहीं देने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सौरभ सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट दी जाती है तो वो किसी भी दशा में काम नहीं करेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो-कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ाया

■ कोदो के समर्थन मूल्य में 200 रूपए तथा कुटकी के समर्थन मूल्य में 250 रूपए की वृद्धि

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शनिवार को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। श्री बघेल ने खरीफ 2023 हेतु कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3350 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो तथा कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। राज्य सरकार द्वारा कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। इसलिए छत्तीसगढ़ के मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोदो- कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कोदो का समर्थन मूल्य जो वर्ष 2022-23 में 3000 प्रति क्विंटल था जिसे खरीफ 2023 हेतु बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का समर्थन मूल्य जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल था उसे बढ़ाकर 3350 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कोदो-कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो एवं कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3200 रूपए प्रति क्विंटल और कुटकी का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3350 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है। रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रूपए प्रति क्विंटल के अनुसार उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन अवधि का निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। कोदो-कुटकी एवं रागी का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाएगा।

गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 9.65 करोड़ रूपए अंतरित किए। इस राशि में गोबर विक्रेताओं को 4.93 करोड़ रूपए, गौठान समितियों को 1.45 करोड़ रूपए, स्व-सहायता समूहों की 1.14 करोड़ रूपए की लाभांश राशि के साथ ही गौठान समिति के सदस्यों को 2.26 करोड़ रूपए की मानदेय राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को आज वितरित की गई राशि को मिलाकर 588.83 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा इस वर्ष धान की खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ होगी राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस साल हम लोगों ने 130 लाख मीटरिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। पिछले साल हम लोगों ने 107 लाख 53 हजार मीटरिक टन धान की खरीदी की थी, इस साल हम धान खरीदी का नया रिकार्ड बनाएंगे। इस साल भी छत्तीसगढ़ के लोग जोरदार दशहरा-दीवाली मनाने वाले हैं। श्री बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्तों का भुगतान भी बिलकुल ठीक समय पर किया जा रहा है। अभी हाल ही में 28 सितंबर को योजना की तीसरी किश्त का भुगतान भी कर दिया गया है। न्याय योजनाओं के अंतर्गत अभी तक पौने दो लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया जा चुका है।

गौठानों में अब तक 138.26 क्विंटल गोबर की खरीदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में अब तक 138.26 क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है, जिसके एवज में पशुपालक किसानों को अब तक 276.53 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 280.04 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 2 किश्तों में लगभग 30 करोड़ रूपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि बोनस का भी भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के मामले में गौठान समिति की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 6453 गौठान स्वावलंबी गौठानों ने अब तक 83 करोड़ रूपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय किया है।

भूपेश सरकार अंतिम सांसें गिन रही अब तो सच स्वीकार करें : साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने धान खरीदी में लगातार झूठ बोलने का आरोप मुख्यमंत्री लगाते हुए कहा कि सरकार अंतिम सांसें गिन रही है वे सत्य बोलने में झिझक क्यों रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को खुलकर बता दें कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 5 साल में प्रति वर्ष केंद्र सरकार ने कितनी राशि दी है और राज्य सरकार ने कितनी राशि दी है?

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न सिर्फ राज्य के कृषकों से धान के समर्थन मूल्य पर उपार्जन की राशि प्रदान करती है। बल्कि धान को चावल में परिवर्तित करने के लिए परिवहन, कस्टम मिलिंग, भंडारण, मंडी शुल्क और उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन और दुकान संचालकों के लिए मार्जिन मनी भी प्रदान करती है। केंद्र सरकार ब्याज की राशि भी आर्थिक लागत में जोड़कर राज्य को प्रदान करती है। यह राशि प्राविधिक सब्सिडी और एडवांस्ड सब्सिडी के रूप में सीधे भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है। इसके अलावा सरप्लस चावल के प्रदाय के लिए राज्य सरकार को सीधे भारतीय खाद्य निगम के द्वारा राशि दी जाती है।

साव ने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर गलतबयानी करके युवाओं को धोखा दे रहे हैं। होर्डिंग में 5 लाख रोजगार का दावा करते थे और विधानसभा में आंकड़े बताते थे कि कितने गिने चुने लोगों को वाकई नौकरी दी गई है। यही स्थिति धान खरीदी के मामले में है। धान खरीदी का पैसा केंद्र सरकार देती है। इस तथ्य को झुठलाने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में बांटने वाले चावल की पूरी आर्थिक लागत का भुगतान भी करती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि क्या राज्य शासन केंद्र से राशि के अंतरण के तथ्य को नकार रहा है? यदि ऐसा है तो राज्य शासन के स्तर पर तथ्य सार्वजनिक किए जाएं।

संक्षिप्त समाचार

10 अक्टूबर तक लग सकती है आचार संहिता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 10 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। रायपुर कलेक्ट्रेट से लेकर मंत्रालय तक सभी विभाग 10 अक्टूबर तक हर वो काम खत्म करने की तैयारी में है, जो आचार संहिता के कारण अटक सकती है। इस बीच शनिवार व रविवार शासकीय अवकाश के कारण जरूर कुछ काम प्रभावित हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग में भी सारी तैयारियां नियमानुसार चल रही है।

रविवि की पूरक परीक्षा 27 अक्टूबर से आवेदन 16 अक्टूबर तक

रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रविवि) ने बीकॉम, बीएससी समेत अन्य कक्षाओं की पूरक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। यह परीक्षा 27 अक्टूबर से शुरू होगी। विवि के मुताबिक यह परीक्षाएं नवंबर तक चलेंगी। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। उल्लेखनीय है कि विवि में दो विषयों में फेल हुए छात्रों की संख्या करीब 72000 है। इस पर लगातार मुख्यमंत्री और राज्यपाल को चिट्ठियां लिखी गई, मांग की गई थी कि दो विषयों में पूरक की पात्रता दी जाए। उच्च शिक्षा विभाग ने पहली बार दो विषयों में फेल हुए छात्रों को पूरक परीक्षा में शामिल होने की पात्रता दी है।

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क व पुल-पुलियां निर्माण गुणवत्ता में श्रेष्ठ

रायपुर। केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों की गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन सड़कों व पुल-पुलियों की जांच व परीक्षण पर गुणवत्तापूर्ण और बेहतर स्थिति में पाया गया। गुणवत्ता समीक्षकों ने गुणवत्तापूर्ण सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत माह सितंबर में छत्तीसगढ़ के 41 सड़कों और पुल-पुलियों का परीक्षण किए थे। परीक्षण में सड़कों और पुल निर्माण गुणवत्तापूर्वक पाया गया था। गुणवत्ता समीक्षकों ने राज्य के 19 पूर्ण हो चुके कार्य, 10 निर्माणाधीन कार्य, 06 मरम्मत का कार्य और 06 पुल का परीक्षण किया था।

अम्बेडकर की नवीन प्रतिमा स्थापना हेतु भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित अम्बेडकर चौक में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की नवीन प्रतिमा स्थापना हेतु आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक श्री कुलदीप जुनेजा, महापौर श्री एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा एवँ जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि अंबेडकर जयंती के दिन यह बात सामने आयी कि बाबा साहब की वर्तमान मूर्ति बहुत पुरानी और खण्डित हो गई है इसलिए इसके स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना की जाये। यह जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई, निगम ने इसके लिए टेंडर निकाला, प्रक्रिया पूर्ण की और मूर्ति भी अब निर्माणाधीन है। आज मूर्ति स्थापना कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है, इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई एवँ शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर चलकर हम समाज और देश को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने हमें जो संविधान दिया है वह सभी देशवासियों के लिए सबसे बड़ी ताकत है।

राजनीतिक अखाड़े में उतरे बसंत, आज निकालेंगे युवा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा

रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जमे वरिष्ठ नेताओं को बदलने और युवा को मौका देने की मांग को रविवार को सुबह 10 बजे गुढियारी हनुमान मंदिर से हठकेश्रनाथ महादेघाट तक युवा अधिकार परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समाजसेवी बसंत अग्रवाल राजनीतिक अखाड़े में उतर रहे है और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे है ताकि वे जनता की सेवा कर सकें।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की जनता पिछले 10-15 सालों से परिवर्तन की मांग करते हुए युवाओं को भी मौका देने की बात करे है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा था। लेकिन इस बार युवाओं ने परिवर्तन जरुर है की मांग को लेकर भाजपा के युवा कार्यकर्ता व समाजसेवक बसंत अग्रवाल को पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की मांग कर रहे है। युवाओं की मांग को देखते हुए वे रविवार को युवा अधिकार परिवर्तन यात्रा निकाल रहे है जिसकी शुरुआत गुढियारी स्थित हनुमान मंदिर सुबह 10 बजे से होगी और यह यात्रा पहाड़ी चौक, भारत माता चौक, तेलघानी नाका, समता कॉलोनी, आमापारा, लाखेनगर, सुंदनगर, रायपुरा चौक होते हुए हठकेश्वर महाघाट पहुंची। जहां भगवान महादेव में पूजा-अर्चना के बाद यात्रा समाप्त होगी। भारत माता चौक में श्री अग्रवाल सभा को संबोधित भी करेंगे जिसमें पीएससी घोटाले से लेकर कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए घोटालों को उजागर किया जाएगा। इस यात्रा में लगभग 15 से 20 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है।

महादेव सट्टा एप मामले में रवि उप्पल के भाई, भाभी को ईडी का नोटिस, कई जगहों पर टीम ने की जांच

भिलाई। भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने महादेव सट्टा एप के मामले में रवि उप्पल के भाई राहुल उप्पल और उसकी भाभी प्रेरणा उप्पल स्मृति नगर के राधिका रॉयल पेंट हाउस पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में दोनों को 27 सितंबर को बयान के लिए बुलाया गया था। सूत्रों के अनुसार ईडी ने शुक्रवार को भिलाई में करीब आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर जांच की है। टीम गुपचुप तरीके से भिलाई पहुंची। ईडी की टीमें जांच-पड़ताल के बाद लौट गईं। ईडी की टीम ने भिलाई के नेहरु नगर स्थित ऑर्बिट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दबिश दी है। बताया जा रहा है कि पहले यह जूस कंपनी सौरभ चंद्राकर के भाई गीतेश चंद्राकार चलाता था लेकिन बाद फरवरी 2022 में गीतेश चंद्राकर ने जूस कंपनी को बेच दिया और जो वर्तमान में इसका डायरेक्टर सौरभ जैन और शुभम गोस्वामी से ईडी ने पूछताछ करने के साथ ही कुछ दस्तावेज लेकर गई है।

महादेव सट्टा एप्प के संचालक की शादी के देश भर में चर्चा

13 फरवरी को भिलाई में अपने घर के

पड़ोस में रहने वाली लडकी से सगाई हुई जिसमे सौरभ चंद्राकार ने अपनी मंगेतर को 35 करोड़ रुपये की अंगूठी रिंग सेरेमनी पर मलेशिया में पहनाया और 14 फरवरी यानि वैलेनटाइन डे के दिन मलेशिया में समुंदर के बीच में एक क्रूज पर सात फेरे लिया। इस शादी में सौरभ ने कई करोड़ रुपए खर्च किए। इस शादी में भिलाई दुर्ग के करीब 350 लोगों को शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा गया था। शादी को गोपनीय रखने के लिए कार्ड में वर और वधु दोनों के नाम को बदल दिया गया था। लेकिन इस कार्ड में माता पिता का नाम सही था। सौरभ चंद्राकर की शादी में 24 से अधिक बॉलीवुड सेलिब्रिटी मुंबई से दुबई पहुंचे थे और इस शादी में लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया था।

दुर्ग पुलिस ने अब तक ऑनलाइन सट्टे पर की कार्रवाई

महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है जिसमे 34 स्थानों पर रेड की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अब तक महादेव सट्टा में 26 मामले दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस ने 194 ऑनलाइन सटोरियों की गिरफ्तारी की है पुलिस ने सटोरियों के पास से 78 लैपटॉप और 371 मोबाइल बरामद किया है। ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल 231 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। फ्रीज किए बैंक खाते में दो करोड़ 40 लाख से अधिक की राशि जमा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से मिले हिसाब किताब में अब तक एक अरब से अधिक की राशि के लेन-देन का खुलासा किया है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का किया शुभारंभ

■ घर से कॉलेज आने-जाने के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क मिलेगी परिवहन सुविधा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढने वाले छात्र-छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा पर अमल करते हुए आज इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढने वाले एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने योजना के शुभारंभ पर छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कॉलेजों में पढने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने-जाने के लिए शासन की ओर से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी वादे के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह यह समझ सकता हूं कि दूर-दराज से कॉलेज पढने के लिए आने-जाने में विद्यार्थियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का वादा हमारे घोषणा पत्र में भी था। आज से इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढने वाले 01 लाख से ज्यादा नियमित विद्यार्थियों को लाभ होगा। इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्ययभार आएगा, इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा एवं आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र वेबसाईट पर कॉलेज और रूट के साथ बस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज लॉग इन कर सभी विवरणों की जांच के पश्चात् आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करेगा। स्वीकृत छात्र लॉग इन कर क्यूआर कोड युक्त अपना बस पास डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बस कंडेक्टर द्वारा पास की जांचकर घर से महाविद्यालय, महाविद्यालय से घर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना के तहत छात्रों को घर से महाविद्यालय तक आने-जाने में सुविधा होगी। निःशुल्क परिवहन से छात्रों को उच्चशिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। यह योजना छात्रों के लिए आर्थिक रूप से भी मददगार होगी।

भूपेश बघेल ने की जातिगत जनगणना कराने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जातीय जनगणना को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार साल 2021 की जनगणना अब तक क्यों नहीं करा रही है।

कांकेर में प्रियंका गांधी के जातीय जनगणना की मांग को सीएम भूपेश बघेल ने भी हवा दे दी हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा से कई सवाल किए। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43 प्रतिशत से ज्यादा हैं, क्या भाजपा को इस बात का विश्वास नहीं हैं ? भाजपा 2021 में होने वाली जनगणना क्यों नहीं करा रही है। जब जनगणना हो सकती है, आर्थिक सर्वेक्षण हो सकता है। भूपेश बघेल ने कहा बिहार सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण कर सकती है तो केंद्र सरकार जनगणना क्यों नहीं कर सकती?

छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना की मांग प्रियंका गांधी ने अपने कांकेर दौरे के दौरान किया। वहां प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में साल 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना कराई जाएगी। प्रियंका गांधी ने पंचायत महासम्मेलन में जातीय जनगणना को लेकर भाजपा पर कई आरोप लगाए। प्रियंका ने कहा कि भाजपा जाति जनगणना कराने से पीछे क्यों हट रही है ? प्रियंका ने कहा कि बिहार में 84 प्रतिशत ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। बिहार की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी जाति जनगणना कांग्रेस सरकार कराएगी।

छत्तीसगढ़ में बिखरता जेसीसीजे, क्यों छोड़कर जा रहे पार्टी के नेता

रायपुर। हाल ही में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के तीन नेता कांग्रेस में शामिल हुए। ये तीनों साल 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे से विधायक प्रत्याशी थे। इनमें गीतांजलि पटेल, चंद्रपुर, खुज्जी विधानसभा से जनरल सिंह भाठिया, मोहला मानपुर से संजीत ठाकुर। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ देने के बाद जेसीसीजे विधानसभा चुनाव 2023 में कैसे जंग लड़ेगी ?

विधानसभा चुनाव 2018 में ऐतिहासिक परिवर्तन छत्तीसगढ़ राजनीति में देखने को मिला। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट के रूप में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी का आगाज हुआ था। इस पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा थर्ड मोर्चे के रूप में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इक्का-दुक्का राजनीतिक दल या निर्दलीय उम्मीदवार एक दो सीट हासिल करते आए थे लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे ने थर्ड मोर्चे के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के नेतृत्व में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जोगी) ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। उस समय केवल दो साल पुरानी इस पार्टी ने 5 सीटें जीतीं। दो सीटों पर सहयोगी बसपा ने जीत हासिल की।

जेसीसीजे से भले ही नेता नाता तोड़ रहे हो लेकिन अमित जोगी पार्टी को बचाने जद्दोजेहद कर रहे हैं। अमित जोगी ने अभी हिम्मत नहीं आ रही है वह लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जेसीसीजे के प्रदेश प्रवक्ता भगवानु नायक कहते हैं कि जोगी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है बल्कि पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। इसका उदाहरण प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अमित जोगी की सभा में उमड़ती भीड़ के रूप में देखा जा सकता है। अमित जोगी ने पाटन विधानसभा से चुनावी शंखनाद किया है। अब अजीत जोगी की तरह अमित जोगी को भी देखने और सुनने हजारों की संख्या ने लोग सभाओं में पहुंच रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता भगवानु नायक ने कहा इस बार जेसीसीजे 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

कांग्रेस का कहना है कि अजीत जोगी ने कांग्रेस से बाहर जाने के बाद पार्टी का गठन किया था। विधानसभा चुनाव में जिन जोगी कांग्रेस के नेताओं ने जीत हासिल की। उनकी पहचान कांग्रेस नेता के तौर पर थी। इसका

फायदा भी उन नेताओं को मिला था। जोगी के निधन के बाद पार्टी उद्देश्यहीन हो चुकी है। इस पार्टी को पहले ही भाजपा की बी टीम के रूप में जनता जानती है। अजीत जोगी के समय जो थोड़ी बहुत इस पार्टी की पहचान थी वह भी अब खत्म हो चुकी है।

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा जो कांग्रेस के नेता जोगी के समय जेसीसीजे में गए थे अब उनके निधन के बाद वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे की भूमिका शून्य हो गई है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। बाकी दूसरे दल महज खानापूर्ति के लिए होंगे।

अमित जोगी से जुड़ नहीं पा रहे कार्यकर्ता- जेसीसीजे का छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा बताते हैं कि जो नेता जोगी कांग्रेस से जुड़े थे, वह शायद अजीत जोगी के जाने के बाद अपने आप को अनकंफरटेबल महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बिना अजीत जोगी के जोगी कांग्रेस अधूरा है। पहले और आज की स्थिति में काफी अंतर है। जोगी कांग्रेस के भविष्य को लेकर उन नेताओं में संशय की स्थिति है। शायद वे अमित जोगी के साथ अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि वे जोगी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं।

भाजपा का कांग्रेस पर नेताओं को प्रलोभन देने का आरोप- भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों को लोकतांत्रिक ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार जोगी कांग्रेस के नेताओं पर लगातार दबाव बना रही है। उन्हें उलझा रही है, फंसा रही है, उन्हें प्रलोभन दे रही है। वे चाहते है कि कैसे भी जोगी कांग्रेस टूट जाए खत्म हो जाए और यदि इसके लिए कोई दोषी है तो भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार दोषी है।पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान थर्ड फ्रंट ने लगभग 14 से 16 फीसदी वोट पाए थे। जिसमें जेसीसीजे, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित अन्य दल शामिल थे। इस बार यह सभी कुछ बेहतर कर पाएंगे इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। जानकार बताते हैं कि सर्व आदिवासी समाज इस विधानसभा चुनाव में तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। उनकी हमर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के दोनों प्रमुख दल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। खासकर बस्तर सहित लगभग 30 आदिवासी सीटों पर इनका खास असर देखने को मिल सकता है।

भाजपा के एक फैसले ने तेलंगाना की बाजी पलट दी

अजय सेतिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में जाकर कहा कि मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (पूर्व नाम टीआरएस) को एनडीए में शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगले ही दिन केसीआर के बेटे के.टी. रामाराव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उलटे भाजपा के नेताओं ने उन्हें एनडीए में शामिल होने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। अब कौन झूठ बोल रहा है, यह तो पता नहीं लेकिन पिछले कुछ महीनों में केसीआर दिल्ली आए जरुर थे, लेकिन उन्होंने भाजपा के नेताओं में से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मुलाक़ात की थी। लेकिन इन दोनों के परस्पर विरोधी दावों के बीच हैदराबाद में आम लोगों की धारणा यह है कि दोनों पार्टियों में गुप्त समझौता हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनवाने के लिए बीआरएस के समर्थन की कीमत पर तेलंगाना की बलि दे दी है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि केसीआर की नाक में दम करने वाले ओबीसी के बड़े नेता के रूप में उभर रहे बंडी संजय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर अचानक रेड्डी समुदाय के कृष्ण रेड्डी को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। जबकि राज्य में ओबीसी वोट 52-53 प्रतिशत और रेड्डी समुदाय के वोट सिर्फ 6-7 प्रतिशत हैं। बंडी संजय ओबीसी में सर्वाधिक प्रभाव रखने वाली मुनुरु कापू जाति से ताल्लुक रखते हैं। छह महीने पहले तक माना जा रहा था कि भाजपा केसीआर को सीधी टक्कर देगी। कांग्रेस को रेस से बाहर माना जा रहा था, लेकिन भाजपा के भीतर हुए इस घटनाक्रम से बाजी पलट गई है। कांग्रेस टक्कर में आ गई है, और भाजपा टक्कर से बाहर हो गई है। बंडी संजय को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए जाने के अलावा एक घटनाक्रम और हुआ है, जिसने भाजपा और बीआरएस में गोपनीय समझौते की धारणा बनाई है, वह घटनाक्रम है केसीआर की बेटी कविता को दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार नहीं किया जाना। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कविता को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि मार्च में कई दौर की पूछताछ के बाद 15 सितंबर को भी कविता को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले कविता ने अपने सारे मोबाईल फोन भी ईडी को सौंप दिए थे। कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचीबाबू गोरान्ता ने ईडी की पूछताछ में पुष्टि की थी कि कविता की केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ अच्छी समझ थी। तेलंगाना में यह धारणा जोर पकड़ रही थी कि कविता को जल्द ही शराब घोटाले की दलाली में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बंडी संजय के प्रदेश भर के दौरों से जब भाजपा केसीआर के विकल्प के तौर पर देखी जाने लगी थी, तब हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण भी हो रहा था। तेलंगाना की लगभग 4 करोड़ आबादी में 52 प्रतिशत पिछड़े और अन्य पिछड़े हैं, जबकि मुस्लिम 12 प्रतिशत और ईसाई 1 प्रतिशत से कुछ ज्यादा हैं। बंडी संजय की लोकप्रियता बढ़ते ही पिछड़ा वर्ग उन्हें केसीआर के विकल्प के तौर पर देखने लगा था। भाजपा ने बंडी संजय के राज्य की कमान छीन कर जैसे ही कृष्ण रेड्डी के हाथ में दी, कांग्रेस ने ओबीसी वोटों को लुभाने के लिए कम्युनिटी कनेक्ट ड्राईव शुरू कर दिया है। जिसमें अपने तीन बड़े ओबीसी नेताओं और अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत, सिद्धारमैया और भूपेश बघेल को तेलंगाना चुनावों में ड्यूटी पर लगा दिया है। पिछड़ों का वोट बैंक भाजपा की तरफ खिसकता देख केसीआर सरकार ने जून में पिछड़ों को लुभाने के लिए उनको आर्थिक मदद पहुँचाने की नई कल्याण योजना शुरू की थी, यह 100 प्रतिशत सब्सिडी के साथ आर्थिक सहायता योजना है, जिसमें बीसी लाभार्थी परिवार के एक सदस्य को एक लाख रुपये की एकमुश्त सहायता का प्रस्ताव है।

जातीय बहुसंख्यकवाद की राजनीति

संजय तिवारी

हमारे देश की राजनीति में कुछ भी सीधा सपाट नहीं है। सब उलझा-उलझा और विरोधाभासों से भरा है। जैसे संवैधानिक रूप से हम एक सेकुलर देश हैं लेकिन इस सेकुलर देश में रिलीजियस माइनोरिटी और मेजोरिटी भी हैं। हमारा संविधान सभी नागरिकों को अवसर की समानता देने की बात करता है लेकिन समय समय पर हम आरक्षित वर्ग पैदा करके इस अवसर की समानता को कम करते रहते हैं। संवैधानिक रूप से किसी भी नागरिक के साथ जाति, भाषा या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता लेकिन हम सवर्ण, पिछड़ा और दलित के नाम पर एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने को क्रांति समझते हैं।

ऐसे अनेकों राजनीतिक विरोधाभाषों का यह देश दशकों से शिकार है। इसमें जो सबसे जटिल विरोधाभाष है वह अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक वाला ही है। इस देश में किसे अल्पसंख्यक कहा जाए और किसे बहुसंख्यक ठीक-ठीक इसको तय करना असंभव है। क्योंकि ऐसा करते समय हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि किसी को अल्पसंख्यक या फिर बहुसंख्यक घोषित करते समय हम आधार क्या तय करें? धार्मिक, जातीय या फिर भाषाई?

राजनीतिक विचारकों ने इस पर जितना विचार किया है, उतना ही विरोधाभास गहरा हो गया है। अगर भारत एक देश है और यहां रहनेवाले सब बराबर के नागरिक तो फिर अल्पसंख्यक कौन हुआ भला? लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता। सवाल यहां से शुरु होता है। यहां से भाषा, जाति, धर्म और इन तीनों के बीच उपभाषा, उपजाति और संप्रदायों का जो सिलसिला शुरु होता है तो सामाजिक रूप से हर समुदाय अल्पसंख्यक ही नजर आता है। यहीं से अंग्रेजों से लड़ते हुए %बांटो और राज करो% का पाठ पढ़ चुके राजनेताओं का राजनीतिक दिमाग काम करना शुरु करता है।

एक लंबे समय तक धार्मिक अल्पसंख्यकवाद को भारतीय राजनीति की मुख्यधारा बनाकर रखा गया। इसके विरोध में जब हिन्दुत्व की राजनीति मुखर हुई तो राजा वीपी सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री राजा बीपी मंडल आयोग द्वारा 1979 में बनायी गयी एक पुरानी रिपोर्ट को लागू कर दिया जिसमें जातीय रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान की गयी थी। इस वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत

आरक्षण प्रदान किया गया। लेकिन इसका लाभ समस्त पिछड़े वर्ग के पिछड़ों को न मिलना था और न मिला। लाभ उन्हें मिला जो पिछड़ों में बहुसंख्यक थे।

अल्पसंख्यकवाद की राजनीति के विकल्प में हिन्दू बहुसंख्यकवाद जो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था वह नये प्रकार के जातीय बहुसंख्यकवाद के सामने डमगमा गया। जबसे 2014 में मोदी के नेतृत्व में हिन्दुत्व की राजनीति ने पुनः प्रचंड बहुमत से अपने आपको स्थापित कर लिया तब से जातीय राजनीति से सत्ता सुख लेनेवाले दलों के सामने संकट पैदा हो गया था। वोटों का धार्मिक ध्रुवीकरण सीधे सीधे भाजपा के पक्ष में था क्योंकि भाजपा के अलावा कोई भी धार्मिक बहुसंख्यक को हाथ नहीं लगाना चाहता था। इसकी काट एक बार फिर उसी फार्मूले के तहत खोजी गयी जो वीपी सिंह 1990 में इस्तेमाल कर चुके थे। लीड किया एक और समाजवादी नीतीश कुमार ने। 2021 में जब कोरोना के कारण देश सामान्य जनगणना न करा सका तो 2022 में नीतिश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना करवा दी। इस जाति जनगणना से कुछ स्थापित सत्य लोगों के सामने आ गये जो अभी तक केवल नेताओं को ही पता रहते थे। मसलन किस जाति के कहां कितने वोटर हैं ये हर राजनीतिक दल को पता है। उसी के अनुसार वो अपनी रणनीति भी बनाते हैं परंतु ऐसी बातें सार्वजनिक सतह पर नहीं लाते। लेकिन नीतीश कुमार और उनके सहयोगी तेजस्वी यादव ने ऐसा कर दिखाया। अब जबकि बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट सबके सामने है तो सवाल घूम फिरकर वहीं पहुंच जाता है कि धार्मिक बहुसंख्यकवाद के विरोधी दल जातीय बहुसंख्यकवाद का समर्थन कैसे कर सकते हैं? अगर धार्मिक रूप से बहुसंख्यक का शासन बहुसंख्यकवाद है तो जातीय रूप से बहुसंख्यक का शासन सामाजिक न्याय कैसे हो जाएगा?

दलीय राजनीति करनेवाले नेता इस बात को समझते थे कि भारत में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर किसी जाति की ऐसी हैसियत नहीं है कि वह सिर्फ जाति के आधार पर राजनीतिक नेतृत्व ले सके। इसलिए जातियों का क्लब बनाया गया। जातियों के इन्हीं क्लब का नाम एससी, एसटी और ओबीसी है। लेकिन अब तक का भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि जातियों के ये राजनीतिक क्लब एकजुट होकर किसी के साथ नहीं गये हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव ने ओबीसी राजनीति के नाम पर जो सफलता हासिल की, उसके पीछे उनके साथ ओबीसी जातियों का जुड़ाव नहीं बल्कि यादव मुस्लिम गठजोड़ रहा है। दोनों ही राज्यों में यादव परिवार आज तक ओबीसी समुदाय में शामिल जातियों का नेतृत्व हासिल नहीं कर पाया है। अगर ओबीसी जातियों का ही वोटिंग पैटर्न देखा जाए तो वह ओबीसीवाद से अधिक राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी के साथ है। असल में किसी जाति की जातीय राजनीति उस जाति के नेता से चलती है। मुलायम सिंह यादव या लालू यादव अपने अपने राज्यों में अपनी जाति को इसलिए गोलबंद कर सके क्योंकि उनकी जाति ने उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर देखा। लेकिन यादवों से बाहर ओबीसी समुदाय में शामिल किसी दूसरी जाति ने दोनों यादव परिवारों को नेता मानने की बजाय बीजेपी, कांग्रेस या नीतीश कुमार को महत्व दिया। इसके बावजूद अगर ये दोनों परिवार अपने-अपने राज्यों में सफल रहे तो उसका कारण ओबीसी राजनीति नहीं बल्कि यादव मुस्लिम गठजोड़ ही रहा। अब बिहार में जाति जनगणना के बाद स्वाभाविक है लालू और मुलायम परिवार की ओर से ओबीसी समुदाय का नेता होने की कोशिश की जाएगी लेकिन फिलहाल ऐसा होना संभव नहीं है। दोनों ही राज्यों की राजनीतिक सच्चाई यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कोई जाति यादवों के साथ जाना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश के बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की ओर से इसकी भरपूर कोशिश की गयी थी लेकिन सफल नहीं हो पाये। राजभर और निषाद समुदाय का मुलायम परिवार से अलग होकर भाजपा के साथ मिल जाना इसी बात का उदाहरण है। बिहार की ताजा जाति जनगणना के परिणामों को ही देखें तो कुल 215 जातियों में 190 जातियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 1 प्रतिशत के नीचे है। 7 जातियां तो ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या दो सौ भी नहीं है। भास्कर जाति लिखनेवाले लोग तो सिर्फ 37 हैं। 20 जातियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या हजार के नीचे है। इस तरह 27 जातियां तो ऐसी निकलकर सामने आयी हैं जो लगभग समाप्तप्राय है। संभव है कुछ समय में इनमें से कुछ का अस्तित्व ही मिट जाए।

जाति जनगणना में सिर्फ 25 जातियां ही ऐसी गिनी गयी हैं जिनकी संख्या प्रदेश में अच्छी खासी है। इसमें यादव सबसे अधिक 14.26 प्रतिशत है। इसके बाद दुसाध 5.31 प्रतिशत और रविदासी/चमार 5.25 प्रतिशत है। कुशवाहा 4.21 प्रतिशत, मुस्लिम शेख 3.82 प्रतिशत, ब्राह्मण 3.65 प्रतिशत, मोमिन 3.54 प्रतिशत, राजपूत 3.45 प्रतिशत, मुशहर 3.08 प्रतिशत, भूमिहार 2.86 प्रतिशत, तेली 2.81 प्रतिशत, मल्लाह 2.60 प्रतिशत, बनिया 2.31 प्रतिशत, कानू 2.21 प्रतिशत, धानुक 2.14 प्रतिशत हैं। स्वाभाविक है जो 25 जातियां 2 प्रतिशत से ऊपर हैं वो अपनी जातीय गोलबंदी करेंगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व का ही पैदा होगा। तो क्या आज जो ओबीसी राजनीति की पैरोकारी कर रहे हैं वो इन जातियों का नेतृत्व कर सकेंगे? क्या वहां वही बहुसंख्यक जाति के शासन का सवाल नहीं उठ खड़ा होगा जो हिन्दुत्व की राजनीति के नाम पर खड़ा किया जा रहा है? भारतीय राजनीति की उलटबांसियों में जो एक बात सीधी सपाट दिखती है वह यह कि यहां राजनीति या सार्वजनिक जीवन में जब एक जाति का वर्चस्व कायम होने लगता है तो बाकी सभी जातियां उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। भारत में ब्राह्मणवाद का विरोध हो, ठाकुरवाद का विरोध हो, जाटवाद का विरोध हो या यादववाद का। बिहार, यूपी, हरियाणा सब जगह आपको इसके प्रमाण मिल जाएंगे कि समय समय पर वर्चस्ववादी जाति के खिलाफ कैसे एक स्वर से बाकी जातियां एक हो जाती हैं। किसी एक बड़ी या प्रभावी जाति के खिलाफ अन्य जातियों की यह एकता ही असल में वर्चस्ववादी जाति की राजनीति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए भारत में धार्मिक बहुसंख्यकवाद की राजनीति का भविष्य तो हो सकता है लेकिन जातीय बहुसंख्यकवाद की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-10)

गतांक से आगे...

जिस शरीर रूपी घर में इन्द्रियरूपी पशु पंक्तिवत् खड़े हैं तथा जिसके प्रांगण में तृष्णा रूपी बंदरी विचरण करती रहती है, जिसमें चित्त वृत्तिरूप भृत्यों का समावेश है। ऐसा शरीर रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। जिह्वा रूपी बंदरी से पीड़ित हुआ यह मुख रूपी द्वार इतना भयभीत हो गया है कि आरम्भ में ही दन्तरूपी हड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा यह शरीररूपी घर मुझे प्रिय नहीं लगता है।

हे मुनीश्वर! यह शरीर बाहर एवं अन्दर रक्त एवं मांसादि से संव्याप्त है, तो इस नश्वर शरीर में रमणीयता कहाँ से आई? यदि किसी ने शरत्कालीन बादलों की विद्युत् में एवं गन्धर्व की नगरी में स्थिरता निश्चित की है, तो वह इस नश्वर देह की स्थिरता में विश्वास कर सकता है। बाल्यकाल में गुरु से, माता-पिता से, लोगों से, आयु में बड़े लड़कों से एवं अन्य दूसरे लोगों से भी भय लगता है, अतः यह बाल्यावस्था भय का ही घर है।

युवावस्था के आने पर अपने ही चित्त रूपी गुफा में निवास करने वाले, भिन्न-भिन्न तरह के भ्रमों में फँसाने वाले इस काम रूपी पिशाच से बलपूर्वक विवश होकर व्यक्ति पराजय को प्राप्त हो जाता है। वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर उन्मत्त की भाँति काँपते हुए व्यक्ति को देखकर दास, पुत्र-पुत्रियाँ, स्त्रियाँ एवं बन्धु बान्धव भी हँसी करते हैं। वृद्धावस्था में शरीर असमर्थ हो जाने पर इच्छा-आकांक्षाएँ अत्यधिक बढ़ जाती हैं। यह वृद्धावस्था हृदय में दाह प्रदान करने वाली सारी आपत्तियों की प्रिय सहेली है। इस नश्वर जगत् में रहने वाले सांसारिक प्राणी जिस सुख की भावना करते हैं, आखिर वह कहाँ है?

काल आयु को तृण के सदृश काटता ही जा रहा है। वह काल छोटे से तृण एवं रजःकण को महेन्द्र एवं स्वर्णमय सुमेरु जैसे विशाल पर्वतों को भी सरसों के समान बना देने में समर्थ है। यह सभी का संहार करने में सक्षम तथा अपनी उदरपूर्ति के लिए सभी को आत्मसात् करने को उद्यत है। इस काल के द्वारा तीनों लोक आक्रान्त हैं।

यंत्रवत् चञ्चल अङ्गरूपी पिंजड़े में मांस की पुतली की भाँति, स्नायु एवं हड्डियों की ग्रन्थि से बनी हुई इस स्त्रीदेह में ऐसी कौन सी वस्तु है, जो शोभनीय कही जा सकती है? आँखों में स्थित त्वचा, मांस, रक्त एवं अश्रु आदि इन सबको अलग-अलग करके अवलोकन करो; इनमें कौन सी वस्तु आकर्षक प्रतीत होती है ?

यदि कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं, तो फिर व्यर्थ में मोह करने से क्या लाभ है? हे मुने! जो नारी सुमेरु पर्वत की चोटियों से उल्लसित होने वाली भगवती माँ गंगा की चञ्चल गति की भाँति है; जो मुक्ताहार से पूर्णरूपेण सुशोभित देखी गई है; कालचक्र के समीप आने पर उसी नारी के मांस पिण्डरूप स्तन को श्मशान में कुत्ते भक्षण करते हैं।

क्रमशः ...

भारतीय वायु सेना दिवस

दीपक कुमार त्यागी

अपने बुलंद हौसले, अदम्य साहस, पराक्रम व शौर्य के बलबूते सम्पूर्ण विश्व में भारतीय वायुसेना के जांबाजों की अलग ही धाक है, हमारी वायुसेना के जांबाज बेहद विकट से विकट व बेहद विषम परिस्थितियों के बीच एक क्षण में ही दुश्मन को आश्चर्यचकित करके रणभूमि में धूल चटाने में माहिर हैं। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना के जांबाजों के द्वारा बहुत साहसिक कार्यक्रमों का आयोजन करके बेहद गरिमापूर्ण गौरवशाली माहौल में धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना माना जाता है। वैसे भारतीय वायुसेना को देश की सुरक्षा में लगी भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सबसे नया अंग माना जाता है।

8 अक्टूबर 1932 को तत्कालीन भारतीय विधायिका द्वारा भारतीय वायुसेना विधेयक पारित करने के साथ ही वायुसेना अस्तित्व में आई। हालांकि 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना के पहले हवाई दस्ते का गठन हुआ, जो एक नंबर स्कवॉड्रन का हिस्सा बनी। इसमें छह रॉयल एयर फ़ोर्स प्रशिक्षित अधिकारी, 19 हवाई सिपाही और चार वेस्टलैंड वापिति आई.आई.ए. सैन्य सहयोग विमान थे। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर एक नंबर स्कवॉड्रन भारतीय

वायुसेना का एकमात्र संगठन था। उस समय हमारी वायुसेना में 16 अधिकारी और 662 सैनिक थे। वर्ष 1939 में देश के तत्कालीन नीति-निर्माताओं के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि मुख्य बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए पाँच हवाई दस्तों की स्वैच्छिक आधार पर व्यवस्था की जाए। जिसके अनुसार मद्रास (वर्तमान चेन्नई) पहला हवाई दस्ता, बंबई (वर्तमान मुम्बई) में दूसरा, कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में तीसरा, कराची (वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा) में चौथा, कोचिन (वर्तमान कोच्चि) में पाँचवां और बाद में विशाखापट्टनम में छठा हवाई दस्ता बनाया गया।

भारतीय वायुसेना के साहसी जांबाजों ने युद्ध के समय रणभूमि में अपना अतुलनीय योगदान देने के साथ-साथ दुनिया में शांति बहाली के अभियान में भी हमेशा अपना बेहद सराहनीय अनमोल योगदान दिया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों व अन्य प्रकार के सभी मिशनों में तो भारतीय वायुसेना का हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। जिसके चलते सम्पूर्ण विश्व भारतीय वायुसेना की कार्यप्रणाली व वीरता का बेहद कायल है। जब भी देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है चाहे वो केरल की बाढ़ हो या उत्तराखंड त्रासदी हो, इस दौरान वायुसेना के जांबाजों ने हमेशा उच्च कोटि का प्रदर्शन करके लोगों की जान बचाने का कार्य किया है। हमेशा वायुसेना के जांबाजों ने दुर्गम जगह पर राहत सामग्री पहुंचा कर लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने में अपना अनमोल योगदान दिया है। इसके लिए हमारी वीर वायुसेना की जितनी सराहना की जाए वह बेहद कम है।

आज हमारी भारतीय वायुसेना तेजी से समयानुसार अपना आधुनिकीकरण करके विश्व की सर्वोच्च श्रेष्ठ सेनाओं में से एक बन गयी है। आज अपने वीर शौर्यवान महावीर योद्धाओं के बलबूते और देश सेवा एवं देश सुरक्षा का जज्बा लेकर वो सशक्त राष्ट्र प्रहरी बन गयी है। हमारे देश की शान भारतीय वायुसेना की पहचान सम्पूर्ण विश्व में अदम्य साहस, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की अद्भुत क्षमता, निड़रता, जांबाजी, जल्द तैयारी की क्षमता, आक्रामक शैली, पलक झपकते ही शत्रुओं को मार गिराने की क्षमता एवं हमारे देश की नभ सीमा को सुरक्षित रखने की असाधारण क्षमता और अपनी उत्कृष्ट अनूठी सेवा एवं अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था करने वाली जांबाज वायुसेना के रूप में होती है। आज प्रत्येक देशभक्त देशवासी भारतीय वायुसेना के जांबाजों को वायुसेना दिवस की बधाई दे रहा है।

मतदान अधिकार नहीं कर्तव्य

चन्द्र शेखर गंगराड़े

भारत में लोक सभा, विधान सभा, नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, संविधान के अनुच्छेद 326 में मत देने का अधिकार दिया गया है लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें मतदान की पात्रता है, उनमें से कुछ अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं फलस्वरूप राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है। देखने में आया है कि वर्ष 2018 में चतुर्थ विधान सभा के आम निर्वाचन के समय छत्तीसगढ़ में कुल 1 करोड़ 85 लाख 88 हजार 520 मतदाताओं के नामों की सूची थी, किंतु यह अवश्यमभावी है कि कई नागरिक, जिन्हें मतदान की पात्रता थी, उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया था। इसके अलावा ऐसे भी नागरिक हैं, जिनका नाम या तो कहीं पर भी मतदाता सूची में नहीं है और यदि किसी अन्य शहर या राज्य की मतदाता सूची में नाम था भी तो उन्होंने वर्तमान में जहां उनका निवास है, वहां अपना नाम दर्ज नहीं करवाया। फलस्वरूप वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अन्यथा उस स्थिति में मतदाताओं की यह संख्या और अधिक हो सकती थी।

अब यदि हम केवल पंजीकृत मतदाताओं की ही बात करें तो वर्ष 2018 में संपन्न छत्तीसगढ़ विधान सभा के आम चुनावों में कुल 1 करोड़ 85 लाख 88 हजार 520 मतदाता पंजीकृत थे लेकिन इनमें से केवल 1 करोड़ 42 लाख 76 हजार 255 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अर्थात् 43

लाख 12 हजार 265 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया।

प्रश्न यह है कि इतनी अधिक संख्या में लोग मतदान के अधिकार का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। इसका एक कारण तो यह है कि अधिकांश शासकीय कर्मचारी, जिनकी ड्यूटी चुनाव के दौरान अपने निवास स्थान से भिन्न दूसरे स्थान पर रहती है या वे चुनाव ड्यूटी में अथवा अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वे मतदान नहीं कर पाते। दूसरा कारण यह है कि कई व्यक्ति निजी, पारिवारिक, सामाजिक या व्यावसायिक कार्यों से अपने निवास से बाहर रहते हैं। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि अस्वस्थता के कारण भी कुछ लोग मतदान नहीं कर पाते होंगे। लेकिन अधिकांश लोग बिना किसी ठोस कारण के, मतदान करने नहीं जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, यह समझ पाना संभव नहीं है। जबकि भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत निर्वाचन आयोग मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भी विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जाता है ताकि सभी पात्र नागरिक अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकें।

मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग प्रति वर्ष अपने स्थापना दिवस के अवसर पर मतदान दिवस का आयोजन भी करता है। जिसमें सभी लोग मतदान करने की शपथ लेते हैं, बावजूद इसके मतदान के प्रतिशत में वृद्धि नहीं हो रही है। यहां यह कहना प्रासंगिक होगा कि नागरिकों के मत देने के अधिकार के कारण ही सरकार का निर्वाचन होता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी एवं किस पार्टी को विपक्ष में कार्य करना है। इस प्रकार मतदाता के पास सरकार के निर्माण की शक्ति है, अथवा यदि यह कहा जाये कि मतदाता सरकार का मालिक है, या उसका भाग्य विधाता है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। इसलिए हमें चाहे कोई भी, कितना ही जरूरी कार्य क्यों न हो, मतदान करने अवश्य जाना चाहिए और यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है तो मतदाता सूची में नाम अवश्य शामिल कराना चाहिए ताकि हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

चतुर्थ छत्तीसगढ़ विधान सभा के चुनाव परिणामों पर यदि गौर किया जाये तो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हार-जीत का अंतर कहीं-कहीं 5 प्रतिशत से कम, तो कहीं-कहीं 10 प्रतिशत के आस-पास रहा और यदि मतदान का प्रतिशत 90 प्रतिशत तक पहुंच जाये तो परिणाम में भी अंतर आ सकता है। इस प्रकार वोट न देने से, मतदान के परिणाम भी प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह भी बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि मतदान के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं में काफी रूचि रहती है और वे प्रातःकाल से ही मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं में मतदान के प्रति उदासीनता का भाव देखा जा सकता है। वर्ष 2018 के आम चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अधिक रहा जबकि कुल मतदान प्रतिशत 76।35 प्रतिशत था अर्थात् शहरी क्षेत्रों का मतदान का प्रतिशत 70 प्रतिशत के आस-पास रहा।

इसलिए आईये हम सब यह संकल्प लें कि अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करेंगे और एक नागरिक के रूप में प्राप्त इस अधिकार का उपयोग, कर्तव्य के रूप में करेंगे और देश तथा सरकार के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

हिन्द स्वराज्य

सत्याग्रह-आत्मबल

प्रश्न- आप जिस सत्याग्रह या आत्मबल की बात करते हैं, उसका इतिहास में कोई प्रमाण है? आजतक दुनिया का एक भी राष्ट्र इस बल से ऊपर चढ़ा हो, ऐसा देखने में नहीं आता। मारकाट के बिना बुरे लोग सीधे रहेंगे ही नहीं, ऐसा विश्वास अभी भी मेरे मन में बना हुआ है।

उत्तर- कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। दया धरम को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाँड़िये, जब जग घट में प्रान॥ मुझे तो यह वाक्य शास्त्र-वचन जैसा लगता है। जैसे दो और दो चार ही होते हैं, उतना ही भरोसा मुझे ऊपर के वचन पर है। दया बल आत्मबल है, सत्याग्रह है। और इस बल के प्रमाण पग-पग पर दिखायी देते हैं। अगर यह बल नहीं होता, तो पृथ्वी रसातल (सात पातालों में से एक) में पहुँच गयी होती। लेकिन आप तो इतिहास का प्रमाण चाहते हैं। इसके लिए हमें इतिहास का अर्थ जानना होगा। इतिहास का शब्दार्थ है-ऐसा हो गया। ऐसा अर्थ करें तो आपको सत्याग्रह के कई प्रमाण दिये जा सकेंगे। इतिहास जिस अंग्रेजी शब्द का तरजुमा है और जिस शब्द का अर्थ बादशाहों या राजाओं की तवारीख होता है, उसका अर्थ लेने से सत्याग्रह का प्रमाण नहीं मिल सकता। जस्ते की खान में आप अगर चाँदी ढूंढ़ने जायँ, तो वह कैसे मिलेगी? हिस्टरी में दुनिया के कोलाहल की ही कहानी मिलेगी। इसलिए गोरे लोगों में कहावत है कि जिस राष्ट्र की हिस्टरी (कोलाहल) नहीं है वह राष्ट्र सुखी है। राजा लोग कैसे खेलते थे, कैसे खून करते थे, कैसे वैर रखते थे, यह सब हिस्टरी में मिलता है। अगर यही इतिहास होता, अगर इतना ही हुआ होता, तब तो यह दुनिया कब की डूब गयी होती। अगर दुनिया की कथा लड़ाई से शुरू हुई होती, तो आज एक भी आदमी जिन्दा न रहता। जो प्रजा लड़ाई का ही भोग (शिकार) बन गयी, उसकी ऐसी ही दशा हुई है। आस्ट्रेलिया के हब्शी लोगों का नामोनिशान मिट गया है। आस्ट्रेलिया के गोरों ने उनमें से शायद ही किसी को जीने दिया है। जिनकी जड़ ही खतम हो गयी, वे लोग सत्याग्रही नहीं थे। जो जिन्दा रहेंगे वे देखेंगे कि आस्ट्रेलिया के गोरे लोगों के भी यही हाल होंगे। जो तलवार चलाते हैं उनकी मौत तलवार से ही होती है।

क्रमशः ...

मुसलमानों में भी जाति आधारित गणना होनी चाहिए

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना के मसले पर सियासत शुरू हो गई है। योगी सरकार पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी विरोधी नेता और गठबंधन तो हो-हल्ला मचा ही रहे हैं। भाजपा के सहयोगी दलों के नेता भी इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना मसले पर भले ही योगी सरकार और बीजेपी अलग-थलग पड़ गई हो, लेकिन वह विरोधियों के सामने 'हथियार' डालने को तैयार नहीं हैं। फिर भी इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी जातीय जनगणना की वकालत करने वालों को भले ही हिन्दू एकता के लिए खतरा बता रही हो, लेकिन बेचैनी उसकी भी बढ़ी हुई है क्योंकि यह वह आग है जिसमें सबका 'झुलसना' तय है। इस आग में कौन अपनी सियासी रोटियां सेंकने में सफल होगा, यह समय बतायेगा। परंतु यह भी तय है कि इसका फैसला चंद महीनों के भीतर होने वाले तीन राज्यों के विधान सभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव हो जायेगा। लेकिन काट हर चीज की होती है, इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि जातीय जनगणना की मांग को हवा देकर किसी पार्टी का सियासी सफर थम जायेगा या फिर उसका ग्राफ बेतहाशा बढ़ जायेगा। बिहार में इसकी बानगी दिखने भी लगी है, वहां पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार कैसे इतने लम्बे समय से सीएम बने हुए हैं, जबकि बिहार में उनकी कुर्मी जाति की भागेदारी मात्र दो-ढाई प्रतिशत ही है। इसी प्रकार लालू यादव के परिवार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि बिहार में यादवों की भागीदारी मात्र 14.27 फीसदी हैं, लेकिन यह परिवार बिहार में लम्बे समय से राज कर रहा है। क्यों नहीं लालू या नीतीश की पार्टी द्वारा 19.65 भागीदारी वाले दलित नेता को सीएम नहीं बनाया जाता है? इसी प्रकार 17.70 फीसदी मुसलमानों में से

किसी को अभी तक सीएम की कुर्सी क्यों नहीं नसीब हुई? बीजेपी सवाल खड़ी कर रही है कि क्यों लालू और नीतीश ही हर बार उनकी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा होते हैं।

बहरहाल, जातीय जनगणना की सियासत में पिछड़ों को सियासी फायदा जरूर हो सकता है क्योंकि एक अनुमान के अनुसार यूपी में कुल जनसंख्या में पिछड़ों की आबादी करीब 60 फीसदी से अधिक बताई जाती है। हालांकि 1931 की जनगणना के बाद ओबीसी आबादी के जातिवार विभाजन का कोई प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं था, लेकिन 2001 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राजनाथ सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री हुकुम सिंह की अगुवाई वाली समिति ने राज्य में 79 ओबीसी की आबादी के आधार पर 7.56 करोड़ की गणना की थी। ऐसे में पिछड़ा समाज के वोटरों को लुभाने के लिए कई दल अधिक संख्या में पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकते हैं। मगर यह सब इतना आसान नहीं होगा।

इसी मुद्दे पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से यूपी में भी जातीय जनगणना कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी पहले से ही ओबीसी को हक दिलाने के लिए मुखर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तो हर समय जातीय जनगणना का राग अलापते रहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी के जो नेता जातीय जनगणना के लिए हायतौबा मचा रहे हैं उनकी यूपी में लम्बे समय तक अपनी सरकारें रह चुकी हैं, परंतु तब इन्हें जातीय जनगणना कराये जाने की जरूरत नहीं लगी। पर अब सबके ऊपर जातीय जनगणना का भूत सवार है। खास बात यह है कि यह नेता हिन्दुओं की कुल आबादी में कितने प्रतिशत दलित, पिछड़े और अगड़े हैं, इसकी तो गणना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों में कितने अगड़े-पिछड़े हैं, इसका पता लगाना यह जरूरी नहीं समझते हैं। जबकि हिन्दुस्तान में मुसलमानों के बीच भी ठीक वैसे ही जातिवाद का जहर फैला हुआ है, जैसे हिन्दुओं में फैला है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लालच में कुछ नेताओं को यह दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुसलमानों में जाति के आधार पर कोई भेद ही नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमानों में भी जातियां तो हैं, लेकिन उनमें उतने गंभीर मतभेद हैं नहीं, जितना कि हिंदुओं में हैं। मुसलमानों में जातिवादी भेदभाव की बात की जाए तो भारतीय मुसलमान मुख्यत: तीन जाति समूहों में बंटा हुआ है। इन्हें अशराफ, अजलाफ और अरजाल कहा जाता है। ये जातियों के समूह हैं, जिसके अंदर अलग-अलग जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होते हैं, वैसे ही अशराफ, अजलाफ और अरजाल को देखा जाता है। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पसमांदा मुस्लिम आंदोलन के नेता अली अनवर अंसारी कहते हैं कि अशराफ में सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल जैसी उच्च जातियां शामिल हैं। मुस्लिम समाज की इन जातियों की तुलना हिंदुओं की उच्च जातियों से की जाती है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल हैं। दूसरा वर्ग है अजलाफ। इसमें कथित बीच की जातियां शामिल हैं। इनकी एक बड़ी संख्या है, जिनमें खास तौर पर अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी जैसी कई जातियां शामिल हैं। कुरैशी मीट का व्यापार करने वाले और अंसारी मुख्य रूप से कपड़ा बुनाई के पेशे से जुड़े होते हैं। हिंदुओं में उनकी तुलना यादव, कोइरी, कुर्मी जैसी जातियों से की जा सकती है। तीसरा वर्ग है अरजाल। इसमें हलालखोर, हवारी, रज्जाक जैसी जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में मैला ढोने का काम करने वाले लोग मुस्लिम समाज में हलालखोर और कपड़ा धोने का काम करने वाले धोबी कहलाते हैं। इन मुसलमान जातियों का पिछड़ापन आज भी हिंदुओं की समरूप जातियों जैसा ही है। मुसलमानों में भी जाति प्रथा हिंदुओं की तरह ही काम करती है। विवाह और पेशे के अलावा मुसलमानों में अलग-अलग जातियों के रीति रिवाज भी अलग-अलग हैं। मुसलमानों में भी लोग अपनी ही जाति देखकर शादी करना पसंद करते हैं। मुस्लिम इलाकों में भी जाति के आधार पर कॉलोनियां बनी हुई दिखाई देती हैं। कुछ मुसलमान जातियों की कॉलोनी एक तरफ बनी हुई है, तो कुछ मुसलमान जातियों की दूसरी तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में तुर्क, लोधी मुसलमान रहते हैं। उनके बीच काफी तनाव रहता है। उनके अपने-अपने इलाके हैं। राजनीति में भी ये देखा जाता है। इस संबंध में राज्यसभा सांसद रहे अली अनवर अंसारी कहते हैं कि जीने से लेकर मरने तक मुसलमान जातियों में बंटा हुआ है। शादी तो छोड़िए, एक-दो अपवादों को छोड़कर इनके बीच रोटी-बेटी का रिश्ता भी नहीं है। जाति के आधार पर कई मस्जिदें बनाई गई हैं। गांव-गांव में जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान बनाए गए हैं। हलालखोर, हवारी, रज्जाक जैसी मुस्लिम जातियों को सैयद, शेख, पठान जातियों के कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं दी जाती।

राजस्थान में पांच पार्टियों ने बढ़ाई भाजपा-कांग्रेस की टेंशन

राहुल संपाल

राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अगले कुछ दिनों में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस पूरी जोर शोर के साथ मैदान में डटे हुए हैं। पिछले 30 सालों में कभी भाजपा, तो कभी कांग्रेस राज्य की सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय दल भी दमदारी के साथ मैदान में उतर रहे है। यह पांच दलों का यह तीसरा मोर्चा राज्य में 50 से ज्यादा सीटों पर गणित बिगाड़ सकता है। इस चुनाव आम आदमी पार्टी, बीएसपी, आरएलपी, भारतीय आदिवासी पार्टी (बीटीपी), माकपा और एमआईएमआईएम जैसी पार्टियों के नेता तो 100 से ज्यादा सीटों पर टक्कर बता रहे हैं। अगर इन पार्टियों ने चुनाव दमदारी से उतरी तो सरकार बनाने में यह किंगमेकर साबित हो सकती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन राष्ट्रीय दल बनने के बाद आप पूरी जोश के साथ मैदान में उतर रही है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के कारण पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। खासतौर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझूनु और अलवर जिलों पर पार्टी खुद को मजबूत मान रही है। कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जो गारंटी देकर गए हैं, उसे घर तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में गठबंधन जैसी कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर शीर्ष नेतृत्व ऐसा कोई निर्णय लेता है, तो अलग बात है। सभी सीटों पर टिकट तय हो चुके हैं बस घोषणा करनी बाकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी पहली बार चुनाव में उतरने की तैयारी में है। ओवैसी राजस्थान की मुस्लिम सीटों पर प्रभाव डालना चाहते हैं। राजस्थान में ऐसी 40 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां औवेसी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। प्रदेश के 18 जिलों में करीब 40 ऐसी सीटें हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनाव हार-जीत में अहम रोल निभाती है। जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, सीकर, झुंझुनूं, चुरू, अलवर, भरतपुर, नागौर जिलों में स्थित सीटों पर हर चुनाव में 16 के आस-पास मुस्लिम प्रत्याशी जीतते रहे हैं। राजस्थान में इस बार आरएलपी पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। पिछले चुनाव में भाजपा को समर्थन देने वाली आरएलपी ने इस बार अकेले मैदान में है। 2018 में आरएलपी ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से तीन जीती थी। वहीं, 7 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। मगर इस बार पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी तो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के नेताओं का मानना है कि लगभग 55 सीटें ऐसी हैं, जहां आरएलपी की मजबूत तैयारी है। इनमें खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की सीटें हैं। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, सीकर और जयपुर ग्रामीण जिले शामिल हैं। वहीं कुछ सीटें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की भी हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी से टूटकर बनी भारतीय आदिवासी पार्टी यानी इस बार राजस्थान के आदिवासी इलाकों में गहरा प्रभाव डाल सकती है। पिछले चुनाव में बीटीपी 11 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से चौरासी और सागवाड़ा दो सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी का दावा है कि वे इस बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इनमें उदयपुर ग्रामीण, गोगुंदा, खेरवाड़ा, झाड़ोल, सलूंबर, डूंगरपुर, आसपुर, चौरासी, घाटोल, सागवाड़ा, बागीदौरा, बांसवाड़ा, गढ़ी, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, धरियावद, पिंडवाड़ा की आदिवासी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। इनमें से 10 से 12 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। बहुजन समाज पार्टी अब तक सबसे ज्यादा 6 सीटें जीती थीं। मगर उसके सभी 6 विधायक चुनाव जीतते ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पार्टी के राजस्थान पदाधिकारी मानते हैं कि इस बार बीएसपी किंगमेकर बनकर उभरेगी। पार्टी ने अब तक छह सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। इनमें नगर, नदबई, धौलपुर, तिजारा, करौली और खेतड़ी सीटें शामिल हैं। बीएसपी 60 सीटों पर विशेष तैयारी है। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, सवाई मोधापुर, दौसा, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों की सीटें हैं।

क्या खतरे में पड़ सकती है आम आदमी पार्टी की मान्यता

अमित शर्मा

दिल्ली में शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो चुकी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले के असली मास्टर माइंड अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पार्टी ने शराब घोटाले में कथित संलिप्तता के आधार पर अरविंद केजरीवाल से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को पार्टी से बाहर करने की मांग भी की है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी शामिल हैं। उन्होंने राजनीति में प्रयोग की बात को देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। भाजपा ने इससे भी आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग तक कर दी है। उसका आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के द्वारा कमाए गए धन से पंजाब और गोवा में चुनाव लड़ा। यह कदाचार है और इस आधार पर पार्टी की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। वहीं, आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शराब घोटाले जैसी कोई चीज कभी हुई ही नहीं है। उनके अनुसार एक भी पैसे का कोई लेनदेन नहीं किया गया है। चूंकि, भाजपा आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद को स्वीकार नहीं कर पा रही है, लिहाजा उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने दोबारा जोर देकर कहा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम करके उनको डिगाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी उनके निशाने पर है, लेकिन पार्टी लगातार आगे बढ़ेगी और अपना ज्यादा विस्तार करेगी। आम आदमी पार्टी राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में भी अपनी शक्ति आजमाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली भाजपा की सचिव सारिका जैन ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से हजारों करोड़ रुपये की अवैध कमाई की। इस कमाई को पंजाब और गोवा विधानसभा के चुनावों में गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और मतदाताओं को अवैध प्रलोभन देकर उन्हें प्रभावित करने का काम किया गया। भारत का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता और यह चुनावी कदाचार के अंतर्गत आता है। सारिका जैन ने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय चुनाव आयोग से यह मांग करती हैं कि भ्रष्टाचार से कमाए गए अवैध धन का दुरुपयोग कर मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने के मामले में स्वत: संज्ञान लें और आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करें। ऐसा करना देश में लोकतंत्र को बचाने में न केवल अपेक्षित है, बल्कि आवश्यक भी है। उन्होंने कहा कि यह दूसरी पार्टियों के लिए भी एक सीख होगी, जो गलत तरीके से चुनावी लाभ हासिल करने की कोशिश करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग में पंजीकृत होते हैं और उन्हें चलाने के लिए पार्टी के संविधान के अलावा चुनाव आयोग की एक नियमावली का पालन करना पड़ता है। चूंकि, राजनीतिक दल पैसों की लेनदेन करने के लिए स्थापित एक कंपनी नहीं होते हैं, लिहाजा उन्हें इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।

जाति जनगणना से देशभर में बदलेंगे चुनावी समीकरण

संजय कुमार

बिहार के जाति जनगणना सर्वे में जो आंकड़े जारी हुए हैं, वे अचंभित करने वाले नहीं हैं। ये लगभग वैसे ही हैं, जैसा आकलन पहले किया जाता था। हां, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय की आबादी में कुछ बढ़ोतरी जरूर दिख रही है। हालांकि अब विपक्ष, खासकर बिहार से जेडीयू और आरजेडी केंद्र सरकार पर देश भर में ऐसा सर्वे कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। केंद्र सरकार का यह तर्क कि सामाजिक, आर्थिक आधार पर जनगणना व्यावहारिक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। सवाल है कि ऐसा करा पाना क्यों संभव नहीं है? क्या इसमें कोई तकनीकी दिक्कत है? हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 2021 में कोरोना महामारी की वजह से नहीं हुई। लेकिन जब भी यह जनगणना होती है, इसमें कई तरह के सवाल पूछे ही जाते हैं। इस जनगणना में यही तो करना है कि आप जिसके घर जाएं, उसकी जाति पूछ लें। वैसे भी उनके आर्थिक आधार का काफी विवरण लिया जाता है। जाति के सवाल से यह भी पता चल जाएगा कि आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से अलग-अलग जातियों का क्या आधार है। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई तकनीकी या व्यावहारिक दिक्कत थी, अलबत्ता यह कहीं ना कहीं टालमटोल जरूर दिखाता है।

बिहार में हुई जाति जनगणना का असर देश पर पड़ेगा तो जरूर, पर यह कहना मुश्किल है कि कितना पड़ेगा। विपक्ष और क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग काफी समय से कर रही हैं। भाजपा इस पर कहीं ना कहीं कन्नी काटती दिखाई पड़ती है। लेकिन जब महिला आरक्षण बिल पारित किया जा रहा था, तो ओबीसी की बात पर भाजपा थोड़ी सी बैकफुट पर गई और आंकड़े लेकर सामने आई। उसने इस बात का जिक्र करना शुरू किया कि उसके कितने मंत्री, सांसद और विधायक ओबीसी से हैं। भाजपा बताने की कोशिश कर रही है कि वह ओबीसी समुदाय के हितों का ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। उधर, तमाम रीजनल पार्टियां ओबीसी के इर्दगिर्द अपनी राजनीति

कर रही हैं। यह सब देखते हुए लगता है कि 2024 के चुनाव में सामाजिक न्याय और ओबीसी का मुद्दा केंद्र में रहने वाला है। जाति जनगणना कोई आज की चीज तो है नहीं। इसकी चर्चा संविधान सभा में हुई थी। लेकिन तब माना जाता था कि जैसे-जैसे हमारा समाज उन्नत होता जाएगा, शिक्षा का प्रसार होगा, उस हिसाब से जातीय भेदभाव कम होते जाएंगे। ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता। अगर बड़े शहरों की बात करें, आज से 30 साल पहले जब मैं दिल्ली पढ़ने आया था, तब मुझे किसी गाड़ी के पीछे जातीय पहचान दिखाई नहीं पड़ती थी। आज जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत और ऐसी तमाम जातियों का जिक्र गाड़ियों के पीछे होता है। क्या ये गाड़ियां अशिक्षित लोगों की हैं? क्या ये गाड़ियां गरीबों की हैं? सच पूछिए तो ये संपन्न लोग हैं और शहरी इलाकों में रहते हैं।

संविधान सभा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 70 साल बाद हमारा समाज किस ओर जाएगा। समाज उस दिशा में गया, जिसमें इसकी डिमांड हुई, और कहीं ना कहीं यह डिमांड जायज भी है। वैसे पहले भी जब जाति जनगणना के आंकड़े नहीं आए थे और जब मंडल कमिशन की सिफारिशें लागू हुई थीं, बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। अगर आप इसके पहले के मुख्यमंत्रियों को देखें, एक-दो अपवाद छोड़कर तमाम लोग अपर कास्ट के रहे। तमाम पार्टियां अपर कास्ट के वोटरों को लुभाने, उनकी गोलबंदी का प्रयास करती थीं। लेकिन मंडल कमिशन की सिफारिशें लागू होने के बाद से तमाम पार्टियां ओबीसी के नाम पर राजनीति करती आई हैं। तो ओबीसी का मुद्दा फोर फ्रंट पर तो पहले भी था। अब तक का आकलन था कि ओबीसी 55 से 56% के आसपास हैं। अब ये जो आंकड़े आए हैं, उनके आधार पर लगता है कि 63% लोग ओबीसी समुदाय से हैं। यानी तमाम पार्टियों का झुकाव जितना पहले था, अब उससे अब और ज्यादा होगा।

रही बात बाकी वर्गों की तो हो सकता है, वे हाशिए पर चले जाएं। सारी पार्टियां, ओबीसी के इर्द गिर्द राजनीति करेंगी। बिहार के एम-वाई फैक्टर में जो वाई है यानी यादव, वह भी ओबीसी का एक हिस्सा है। कुर्मी वोटर भी हैं। भाजपा का जो इतना विस्तार हुआ है बिहार या देश के अलग-अलग राज्यों में, उसमें एक बड़ी वजह उसकी ओबीसी में पैठ है। उसने अपने लोअर ओबीसी वोटरों के बीच जबरदस्त पैठ बनाई है।

तो ऐसा नहीं है कि अभी आंकड़े आए हैं और इसके सहारे ही सारी पार्टियां राजनीति करेंगी। जब आंकड़े नहीं आए थे, तब भी राजनीति हो रही थी। हां, सवर्णों को थोड़ा सा झटका लगा है या लगेगा। कम से कम उन्हें ऐसा लगेगा कि वे धीरे-धीरे हाशिए पर आ रहे हैं। लेकिन पार्टियों को इस बात का आभास होना चाहिए कि किसी एक खास वर्ग या समुदाय के वोट से लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। हो सकता है एक या दो चुनाव में सवर्ण जाति के वोटर थोड़े और हाशिए पर चले जाएं बिहार में, लेकिन आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों को उनका भी समावेश करना पड़ेगा। रही बात चुनावी उम्मीदवारी में ओबीसी की 63% हिस्सेदारी की तो इसमें कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए। जिस 63% आबादी की बात है, उसमें अभी तमाम नेता हैं। बिहार में मुकेश सहनी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा जैसे बहुत से नेता हैं। ये सब 63% के ग्रुप में पैदा हुए नेता हैं। इसलिए नेतृत्व का अभाव नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि पार्टियां तमाम ओबीसी जातियों को रिप्रजेंटेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं या नहीं?

सच्चे किसान वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन

नरेंद्र मोदी

प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं हैं। हमारे देश ने एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है, जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। हमने एक ऐसे महान व्यक्ति को खोया है, जिनका भारत के लिए योगदान हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन भारत से प्रेम करते थे और चाहते थे कि हमारा देश और विशेषकर हमारे किसान समृद्धि के साथ जीवन यापन करें। वे अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली थे और किसी भी करियर का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन 1943 के बंगाल के अकाल से वे इतने द्रवित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि अगर कोई एक चीज, जिसे वे करना चाहेंगे, तो वो है-कृषि क्षेत्र का कायाकल्प।

बहुत छोटी उम्र में, वे डॉ. नॉर्मन बोरलॉग के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा। 1950 के दशक में अमेरिका ने उनसे एक फैकल्टी के तौर पर जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे भारत में रहकर देश के लिए काम करना चाहते थे। आज हम सभी को दशकों पहले की उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में विचार करना चाहिए, जिनका प्रो. स्वामीनाथन ने डटकर सामना किया और हमारे देश को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के मार्ग पर आगे ले गए। आजादी के बाद पहले दो दशकों में, हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे और उनमें से एक थी-खाद्यान्न की कमी। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत अकाल से जूझ रहा था। इसी दौरान प्रोफेसर स्वामीनाथन की दृढ़ प्रतिबद्धता व दूरदर्शिता ने कृषि सेक्टर के एक नए युग की शुरुआत की।

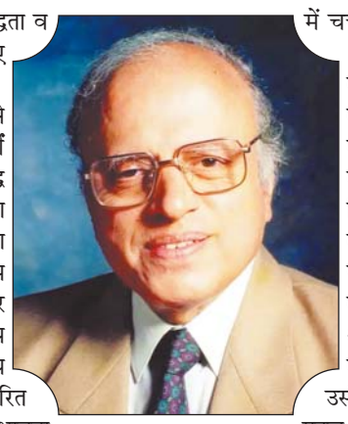

कृषि और गेहूं प्रजनन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके अग्रणी कार्यों से गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसे प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया। इस शानदार उपलब्धि की वजह से उन्हें 'भारतीय हरित क्रांति के जनक' की उपाधि मिली, जो बिल्कुल सही भी है। हरित क्रांति में भारत की 'कैन डू' की भावना झलकती है, यानी कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अगर हमारे सामने करोड़ों चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनोवेशन की लौ जलाने वाले करोड़ों प्रतिभाशाली लोग भी हैं। हरित क्रांति शुरू होने के पांच दशक बाद, भारतीय कृषि पहले से अधिक आधुनिक और प्रगतिशील हो गई है। लेकिन प्रोफेसर स्वामीनाथन द्वारा रखी गई नींव को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने आलू की फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने की दिशा में भी प्रभावी अनुसंधान किया था। उनके शोध ने आलू की फसलों को ठंड के मौसम का सामना करने में भी सक्षम बनाया। आज दुनिया सुपर फूड के रूप में मिलेट्स या श्री अन्न के बारे में बात कर रही है, लेकिन प्रोफेसर स्वामीनाथन ने 1990 के दशक से ही मिलेट्स के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित किया था।

प्रो. स्वामीनाथन के साथ मेरी व्यक्तिगत बातचीत का दायरा बहुत व्यापक था। इसकी शुरुआत 2001 में मेरे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद हुई। उन दिनों गुजरात आज की तरह अपने कृषि सामर्थ्य के लिए नहीं जाना जाता था। हर कुछ साल पर पड़ने वाले सूखे, तबाही लाने वाले चक्रवात और भूकंप ने राज्य की विकास यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया था। उसी दौर में हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की पहल की थी। हमारी कोशिश थी कि हमारे किसानों को मिट्टी को बेहतर ढंग से समझने और समस्या आने पर उसका समाधान करने में मदद मिले। इसी योजना के सिलसिले में मेरी मुलाकात प्रोफेसर स्वामीनाथन से हुई। उन्होंने इस योजना की सराहना की और इसके लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी साझा किए। उनका समर्थन उन लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त था जो इस योजना को लेकर संशय में थे। आखिरकार इस योजना ने गुजरात में कृषि क्षेत्र की सफलता का सूत्रपात कर दिया। मेरे मुख्यमंत्री रहने के दौरान और उसके बाद जब मैंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब भी हमारी बातचीत चलती रही। मैं उनसे 2016 में इंटरनेशनल एग्रो-बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस में मिला और अगले वर्ष 2017 में मैंने उनके द्वारा लिखित दो-भाग वाली पुस्तक श्रृंखला लॉन्च की।

'कुरल' ग्रंथ के मुताबिक किसान वो धुरी हैं, जिसके चारों तरफ पूरी दुनिया घूमती है। ये किसान ही हैं, जो सब का भरण-पोषण करते हैं। प्रो. स्वामीनाथन इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझते थे। बहुत से लोग उन्हें 'कृषि वैज्ञानिक' कहते हैं, यानी कृषि के एक वैज्ञानिक, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि उनके व्यक्तित्व का विस्तार इससे कहीं ज्यादा था। वे एक सच्चे 'किसान वैज्ञानिक' थे, यानी किसानों के वैज्ञानिक। उनके दिल में एक किसान बसता था। उनके कार्यों की सफलता उनकी अकादमिक उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं है; ये लैब के बाहर, खेतों और मैदानों में स्पष्ट रूप से दिखती है। उनके कार्य ने साइंटिफिक नॉलेज और उसके प्रैक्टिकल उपयोग के बीच के अंतर को कम कर दिया। उन्होंने ह्यूमन एडवांसमेंट और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन पर जोर देते हुए हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वकालत की।

यहां मैं विशेष तौर पर ये भी कहूंगा कि प्रो. स्वामीनाथन ने छोटे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उन तक इनोवेशन का लाभ पहुंचाने पर बहुत जोर दिया। वे विशेष रूप से महिला किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति समर्पित थे। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के व्यक्तित्व का एक और पहलू भी है, जो बेहद उल्लेखनीय है। वे इनोवेशन और मेंटोरशिप को बहुत बढ़ावा देते थे। जब उन्हें 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला तो उन्होंने इसकी पुरस्कार राशि का उपयोग एक गैर-लाभकारी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना में किया। आज भी यह फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्य कर रहा है। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को निखारा है और उनमें सीखने और इनोवेशन के प्रति जुनून पैदा किया है। तेजी से बदलती दुनिया में उनका जीवन हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और इनोवेशन की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। प्रोफेसर स्वामीनाथन एक संस्थान निर्माता भी थे। उन्हें कई ऐसे केंद्रों की स्थापना का श्रेय जाता है, जहां आज वाइब्रेंट रिसर्च हो रही है। उन्होंने कुछ समय तक मनीला स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी अहम जिम्मेदारी निभाई थी। दक्षिण एशिया में इस संस्थान का रीजनल सेंटर 2018 में वाराणसी में खोला गया था। मैं प्रो. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के लिए फिर से 'कुरल' ग्रंथ को उद्धृत करूंगा। उसमें लिखा है, ''यदि योजना बनाने वालों में दृढ़ता हो, तो वे वही परिणाम हासिल करेंगे, जो वे चाहते हैं।'' प्रो. स्वामीनाथन एक ऐसे दिग्गज व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही ये तय कर लिया था कि वो कृषि को मजबूत करेंगे और किसानों की सेवा करेंगे। उन्होंने इस संकल्प को बेहद ही रचनात्मक तरीके से और जुनून के साथ निभाया। जैसे-जैसे हम एग्रीकल्चरल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, डॉ. स्वामीनाथन का योगदान हमें निरंतर प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। हमें उन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहना होगा, जो उन्हें बेहद प्रिय थे। इन सिद्धांतों में किसानों के हितों की वकालत करना, साइंटिफिक इनोवेशन के लाभ को कृषि विस्तार की जड़ों तक पहुंचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देना शामिल है. मैं एक बार फिर प्रोफेसर स्वामीनाथन को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।

पिंड दान के लिए हरिद्वार जा रहे तो इन जगहों को देखना ना भूलें

पितृ पक्ष में बहुत सारे लोग पिंड दान के लिए हरिद्वार का रुख करते हैं। वहीं हरिद्वार में गंगा स्नान का भी खास महत्व है। इसलिए ज्यादातर लोग धार्मिक ट्रिप पर हरिद्वार जाते हैं। यहां कई सारे मंदिर और आश्रम है। जहां की सैर मन को सुकून देती है। लेकिन इस धार्मिक ट्रिप पर भी आप बहुत सारी जगहों की सैर कर इस ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। वैसे तो हरिद्वार जाने वाले लोग ऋषिकेश जरूर जाते हैं। लेकिन ऋषिकेश के अलावा भी हरिद्वार में ब्यूटीफुल लोकेशन हैं। जिन्हें एक बार देखना तो बनता है।

चिल्ला रेंज

चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरिद्वार से करीब साढ़े दस किमी दूर है। 250 स्क्वेअर किमी के एरिया में फैले इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई सारे जानवरों को देखने का मौका मिल सकता है। हरिद्वार की ट्रिप पर आप चिल्ला रेंज में जीप सफारी का लुत्फ आसानी से उठा सकते हैं।

बिल्केश्वर महादेव टैंपल

हरिद्वार रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बना है बिल्केशर महादेव टैंपल। इस मंदिर में भगवान शिव की खूबसूरत प्रतिमा बनी हुई है।

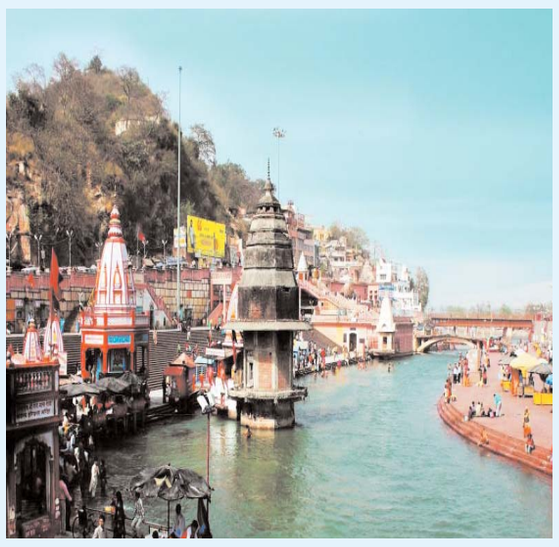

नील धारा पक्षी विहार

हरिद्वार से करीब साढ़े तीन किमी की दूरी पर बना है नील धारा पक्षी विहार। जहां ठंड के वक्त ढेर सारे पक्षी प्रवास के लिए यहां आते हैं। गंगा के किनारे यहां साइबेरियन क्रेव सर्दियों में आसानी से देखे जा सकते हैं। यहां से शिवालिक पहाड़ियों का खूबसूरत प्राकृतिक नजारा भी देखने को मिल जाता है। तो हरिद्वार जाएं तो इस पक्षी विहार की सैर करना ना भूलें।

भीमगोड़ा टैंक और बैराज

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां भीम ने अपने घुटने टेके थे। ये जगह हर की पैड़ी से कुछ ही दूरी पर बनी है।

सती कुंड

हरिद्वार से कुछ किमी की दूरी पर बसा है कनखल। जहां पर सती कुंड बना है। ये एक यज्ञ कुंड है, मान्यता है कि राजा दक्ष के शिव के अपमानित करने पर इसी कुंड में सती कूद गई थीं।

विदेश घूमने का है मन तो जरूर जाएं स्विट्जरलैंड के ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल

हर साल हजारों की तादाद में लोग यूरोप में स्थित इस धरती के इस स्वर्ग को देखने के लिए आते हैं. अगर आप कहीं देश में घूमने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार स्विट्जरलैंड के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए. आइये जानते है कुछ बेहतरीन स्विट्ज़रलैंड के पर्यटन स्थल के बारे में

मैटरहॉर्न

आप स्विट्जरलैंड घूमने जाने की तैयारी कर रहे हो और आप की लिस्ट में मैटरहॉर्न ना हो, यह तो खुद के साथ नाइंसाफी होगी. मैटरहॉर्नजगह ही ऐसी है जिससे हर कोई देखना चाहता है 4478 मीटर मीटर की ऊंचाई पर यह आल्प्स पर्वत के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है जो स्विट्ज़रलैंड तथा इटली के बॉर्डर पर स्थित है. जब आप इतनी ऊंचाई तक खुद चलकर चढ़ते हुए जाएंगे यह एक अलग ही तरह का एडवेंचर होगा. यदि आपको लगता है कि आप चढ़कर नहीं जा सकते तो आप इस पर्वत पर जाने के लिए 'केबल कार' का सहारा भी ले सकते हैं.

स्विस राष्ट्रीय पार्क

स्विस नेशनल पार्क दक्षिण स्विजरलैंड की रेहतियन पर्वत श्रंखला में बसा एक बेहद ही खूबसूरत पार्क है नेशनल पार्क का निर्माण 1 अगस्त सन 1910 में स्विजरलैंड के राष्ट्रीय छुट्टी दिवस पर किया गया था. यह पार्क यूरोप के सबसे पहले बसे पार्कों में से एक है वैसे तो स्विट्जरलैंड पूरा ही बेहद खूबसूरत देश है लेकिन स्विस नेशनल पार्क में आना आपको स्वर्ग में होने का एहसास कराता हैं.

जंगफ्राजोच

जंगफ्राजोच समुन्द्र तल से लगभग चार हजार मीटर ऊंची बर्नीज पर्वत श्रंखला के दो पर्वत जुन्फ्राऊ तथा मोंच को जोड़ने वाला एक प्रमुख पर्यटन स्थल हैं. जुंगफ्राजूच की समुन्द्र तल से ऊँचाई 3463 मीटर ह, इतनी उचाई पर स्थित होन के कारण जंगफ्राजोच यूरोप का शीर्ष भी कहा जाता हैं. यदि आप जुंगफ्राजूच की खूबसूरती का अच्छे से लुत्फ उठाना चाहते है तो आप स्फिंक्स से इसका पूरा नजारा देख सकते हैं. इस जगह की शूटिंग फिल्म हीरो(2003), क्रिश 3 (2023) और इसी साल रिलीज पठान(2025) इसी जगह शूट की गई है.

शिल्थॉर्न

शिल्थॉर्न स्विट्ज़रलैंड की बर्नीज पर्वत श्रंख्लायो में स्थित एक शिखर है जिसकी उचाई 2970 मीटर हैं. हर साल यहाँ हजारो की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं. शिल्थॉर्न की तली में मुर्रेन नामक एक छोटा सा गाँव स्थित है जहाँ से आपको स्चिल्थोर्ण पहुचन के लिए कवल कार मिल जाती हैं केवल कर से इस शिखर पर पहुँचना ही एक अनोखा व रोमांचित करने वाला अनुभव है आप यहां पर स्किंग (skeing) का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं.

ज्यूरिख

स्विट्जरलैंड गए तथा ज्यूरिख नहीं देखा, फिर तो आपने आधा स्विट्जरलैंड ही नहीं देखा. ज्यूरिख एक बहुत ही मनमोहक करने वाला खूबसूरत शहर हैं, यहाँ आपको पुराने भवनों के साथ-साथ नए तरह के भवन भी देखने को मिलते हैं. जीवन जीने के लिए दुनिया के टॉप शहरो में शामिल यह शहर स्विट्ज़रलैंड का सांस्कृतिक व व्यावासिक हब भी हैं, तथा यह इस देश का सबसे बड़ा नगर भी हैं.

द राइन फॉल्स

द राइन फॉल्स स्विट्ज़रलैंड का सबसे प्रमुख झरना या जल-प्रपात हैं. इस झरने में पानी बहुत अधिक मात्रा में तथा तेजी से आता है जिस कारण इसे यूरोप का सबसे शक्तिशाली जल-प्रपात कहा जाता है. इस झरने पर बिजली बनाने के लिए कई बार प्रोजेक्ट शुरू किये गए लेकिन स्थानीय लोगो के अवरोध के बाद इन प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं किया गया. द राइन फॉल्स को 14000 से 17000 पुराना माना जाता हैं.

बर्न

स्विट्ज़रलैंड घूमने की ख्वाइश रखने वाला हर व्यक्ति इसकी राजधानी बर्न के बारे में तो जानता ही हैं. यह एक बेहद ही आधुनिक एवं आकर्षक शहर है जहाँ हर साल लाखो शौलानी घूमने के लिए आते हैं. बर्न में घड़ियाँ बनाने का काम बहुत होता हैं यहाँ की घड़ियाँ आपको संसार के कोने-कोने तक देखने को मिल जाएगी. कहा जाता हैं कि इसका नाम बर्न इटली के एक शहर वेरोना के नाम पर पड़ा था जिसे 11वी शताब्दी के आस-पास बर्न के नाम से जाना जाता था.

लुगानो झील

स्विट्ज़रलैंड जाने वाले हर पर्यटक की लिस्ट में जो एक नाम अवश्य मिलेगा वह है लुगानो झील (Lake Lugano). इस झील को देखने के बाद आप इसे संसार की सबसे सुन्दर व आकर्षक झील तो कहोगे ही साथ में लुगानो को आप पर्यटकों के घूमने के लिए सबसे सुन्दर जगहो में से एक भी कहेंगे.

जिनेवा

जिनेवा के बारे में आपने जरूर बचपन में अपनी किताबो में पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय यहं होने की बजह से यह नगर हमेशा शुर्खियों में रहता हैं. राजनितिक परिपेक्ष से हटकर भी इस शहर में घूमने लायक बहुत अधिक अच्छी खूबसूरत जगह हैं. जिनेवा का ओपेरा हाउस, ऑर्केस्टा तथा झील आदि दुनियाभर से लाखो पर्यटकों का ध्यान अपनी और खीचते हैं.

[भविष्यफल]

मेष
आज का दिन आपके लिए अनुकुल रहेगा। किसानों के लिए दिन अच्छा रहेगा। फसल अच्छी होने से मन प्रसन्न रहने वाला है।

वृष
आज का दिन आपके आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। आपके बेटे को किसी क्षेत्र में अच्छे विकास से आपको खुशी मिलेगी।

मिथुन
आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आज जीवनसाथी किसी जरूरी बात को आपसे शेयर करेंगे। उनकी बात को जरूर समझेंगे।

कर्क
आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। सामाज सेवा से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहने वाला है, आज आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा।

सिंह
आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप नया घर खरीदने का विचार बनायेंगे। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा।

कन्या
आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। कारोबार में आ रही किसी रुकावट का आज समाधान मिल जायेगा।

तुला
आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाला है। किसी बड़ी खुशखबरी से परिवार में उत्सव का माहौल बना रहेगा।

वृश्चिक
आज आपका दिन कॉन्फिडेंस के साथ शुरू होने वाला है। सकारात्मक सोच के साथ व्यापार में निवेश के लिए आज का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है।

धनु
आज का दिन उत्साह से भरपूर रहने वाला है। किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार होने से खुद को बेहतर महसूस करेंगे।

मकर
आज का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लाएगा। नया बिसनेस शुरू करने में आपको सफलता मिलेगी।

कुंभ
आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जिससे आपकी दोस्ती मजबूत बनेगी।

मीन
आज का दिन आपके लिए खुशनुमा पल लेकर आया है। किसी चीज को पाने की कामना आज पूरी होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।

पतझड़ के मौसम में बेहद खूबसूरत हो जाती हैं भारत की ये जगहें

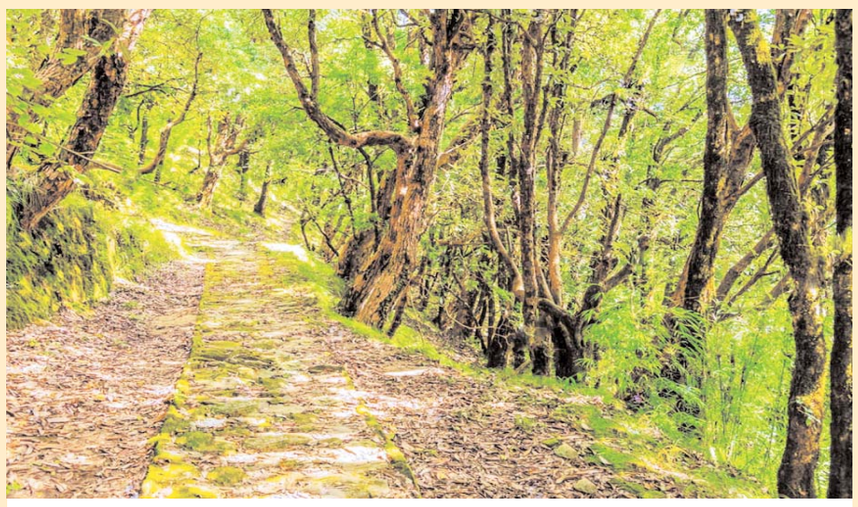

गर्मियों की समाप्ति और सर्दियों की शुरुआत के बीच का मौसम घूमने- फिरने के बेहद अनुकूल होता है। इस दौरान ज्यादातर जगहों की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। ऐसे में कौन सी जगहों की सैर पर निकलें। अगर आप कर रहे हैं इसका प्लान तो एक नजर डालें इन डेस्टिनेशंस पर जहां का नजारा जन्नत से कम नहीं होता।

पतझड़ के मौसम में प्रकृति एक अलग ही खूबसूरत कैनवास तैयार करती है और कुछ जगहों पर इसकी खूबसूरती ऐसी होती है कि जिसे एक बार देखना तो बनता है। गर्मियां खत्म होने की कगार पर हों और सर्दियों की शुरुआत हो रही है, ये मौसम एक अलग ही तरह की राहत देता है। ऐसे मौसम में घूमने का भी एक अलग ही आनंद होता है। अगर आप भी कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में कर सकते हैं शामिल।

सिक्किम

कंचनजंगा पर्वत से घिरा सिक्किम एक बेहद खूबसूरत जगह है उनके लिए जो प्रकृति को करीब से देखने की चाह रखते हैं। सुन्दर फूलों से लदी घाटियां, साफ नीले पानी की झीलें, घने जंगल और खूबसूरत बौद्ध मठ यहां के आर्कषण में चार चांद लगाने का काम करते हैं। यहां का शांत माहौल जगह को और लुभावना बनाता है। अक्टूबर में यहां आना आपके ट्रिप को यादगार बना देगा।

श्रीनगर, कश्मीर

पतझड़ के महीने में घूमने वाली जगहों में कश्मीर भी शामिल है। वैसे तो हर एक सीज़न में कश्मीर का एक अलग ही नजारा कुदरत तैयार करती है। मतलब आप जिस भी सीजन में यहां आएंगे, ऐसा लगेगा कि पहली बार कश्मीर आए हैं। बेमिसाल खूबसूरती से भरपूर और भारत के स्वर्ग नाम से कश्मीर में घूमने वाली जगहों की कमी नहीं। बस जरूरत है तो वक्त और जज्बे की। सर्दियों में यहां घूमना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, तो आप अक्टूबर में यहां आने का प्लान बनाएं और करीब से देखें इस जन्नत को।

बिनसर

उत्तराखंड का मौसम भी अक्टूबर के दौरान बेहद सुहावना होता है। वैसे तो यहां की ज्यादातर जगहें अपनी एक अलग खूबी लिए हुए हैं, लेकिन बिनसर की बात ही कुछ और है। अल्मोड़ा से महज 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिनसर। इस जगह की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं बर्फ के ढके पहाड़ों और हरे-भरे घास के मैदान। बिनसर घूमने के लिए अक्टूबर का महीना बेस्ट होता है।

दार्जिलिंग

दार्जिलिंग को हिल स्टेशन्स की रानी के नाम से जाना जाता है। जहां बिखरी है बेशुमार खूबसूरती। वैसे ये जगह एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी काफी अच्छी है। दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों, टॉय ट्रेन की सवारी के लिए खासतौर से मशहूर है। वैसे तो आप यहां कभी भी आकर एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन पतझड़ के दौरान यहां का अलग ही नजारा आपको देखने को मिलेगा। खानपान के शौकीन हैं, तो यहां के स्थानीय जायकों को चखना बिल्कुल भी मिस न करें।

केरल में घूमने की ये हैं सबसे खूबसूरत जगहें

छुट्टियों में बनाएं विजिट करने का प्लान

घूमने-फिरने के शौकीन लोग अक्सर कहीं न कहीं जाते रहते हैं। परफेक्ट डेस्टिनेशन के तलाश में हैं तो केरल आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहां नेचर की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी।

केरल बहुत ही खूबसूरत राज्य है। यहां एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। यहां अक्सर सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। केरल को देवताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। आप यहां फैमिली ट्रिप या हनीमून के लिए भी जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, केरल के फेमस पर्यटन स्थलों के बारे में।

मुन्नार

अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो मुन्नार आपके लिए बेस्ट आप्शन हो सकता है। इस हिल्स स्टेशन की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मुन्नार चाय बागानों के लिए भी फेमस है। यहां मौजूद इको प्वाइंट पर आप कई तरह की एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं।

वर्कला

वर्कला केरल का प्रसिद्ध स्थल है। यहां के बीच और दूर तक फैले समुद्र की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। यहां पहाड़ और समुद्र के अद्भूत नजारे देखने को मिलते हैं। अगर आप केरल घूमने जाएं, तो वर्कला जाना न भूलें।

फोर्ट कोच्चि

फोर्ट कोच्चि को ओल्ड कोच्चि या वेस्ट कोच्चि के नाम से भी जाना जाता है। आप यहां पैदल घूम सकते हैं। यहां मौजूद डच पैलेस काफी फेमस है। इसके अलावा आप सांता क्रूज कैथेड्रल बैसिलिका, इंडो-पॉर्टूगीज म्यूजियम आदि देख सकते हैं।

वायनाड

वायनाड बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। यहां ऐतिहासिक गुफाएं, झरने और कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं। यहां आपको ठहरने के लिए कमरे भी मिल जाएंगे। आप यहां प्रकृति की सैर और ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं।

अल्लेप्पी

अल्लेप्पी केरल में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यहां साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यह बीच वॉलीबॉल और सर्फिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट ऑप्शन माना जाता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सौ पदक पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली। एशियाई खेलों में भारत के सौ पदक पूरे होने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वह भारतीय दल का 10 अक्टूबर को स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, हर अद्भुत प्रदर्शन ने इतिहास रचा और हमारा हृदय गर्व से भर दिया। मैं दस अक्टूबर को हमारे एशियाई खेलों के दल का स्वागत करूंगा और खिलाड़ियों से बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोग रोमांचित हैं कि हमने 100 पदकों की उपलब्धि हासिल की । उन्होंने कहा, एशियाई खेलों में भारत के लिये महत्वपूर्ण उपलब्धि। मैं हमारे शानदार खिलाड़ियों को बधाई देता हूं जिनके प्रयासों से भारत ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। बता दें कि भारतीय दल ने एशियाई खेलों में सौ पदक पूरे कर लिये जब महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपै को शनिवार को रोमांचक फाइनल में 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

जगन मोहन रेड्डी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पोलावरम सिंचाई परियोजना पर चर्चा की। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों के हित में सीएम ने गृहमंत्री से बात की। सीएम ने राज्य से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की। दोनों नेताओं ने इस दौरान 45 मिनट बैठक की। शाह और जगन की बैठक को लेकर आंध्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में प्रमुख रूप से पोलावरम परियोजना पर चर्चा की गई। शाह से उन्होंने प्रभावी कदम उठाने के लिए अपील की। जगन ने कहा कि शाह यह भी सुनिश्चित करें कि तेलंगाना सरकार साल 2014 और 2017 के बीच आपूर्ति की गई बिजली के लिए अपनी डिस्कॉम से आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन को 7,230 करोड़ रुपये का बकाया चुकाए।

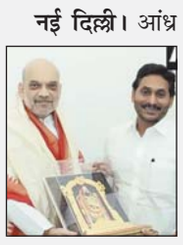

राहुल अगले चुनाव में देश का करेंगे नेतृत्व : शिवकुमार

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद राहुल गांधी के पोस्टरों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी खींचतान के बीच कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अगले चुनाव में देश का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गई है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद सांसद के बारे में जो धारणा बीजेपी ने बनाने की कोशिश की थी, वह बदल गई है। डीके शिवकुमार ने कहा, बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के बारे में जो धारणा बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है, बदल गया है। वह ऐसे नेता हैं जिन पर नजर रहेगी। वह अगले चुनाव में देश का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच गुरुवार से ही सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर जारी है।

लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी एआईएडीएमके : पलानीस्वामी

चेन्नई। अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा कि पार्टी ने तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। पिछले महीने, चेन्नई में एआईएडीएमके मुख्यालय में ईपीएस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय के बाद एआईएडीएमके ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडप्पादी ने तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के दोहरे रुख का हवाला देते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीति है। ईपीएस ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव अलग से लड़ने का फैसला किया ताकि तमिलनाडु के लोगों की आवाज संसद में गूंज सके और राज्य के लोगों के अधिकारों की भी रक्षा की जा सके। ईपीएस ने कहा कि अन्नाद्रमुक का रुख तमिलनाडु और उसके लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में था।

बिहार की तरह कराएंगे जाति जनगणना :गहलोत

राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बिहार में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने के कुछ दिनों बाद बिहार की तर्ज पर चुनावी राज्य में जाति जनगणना कराने की घोषणा की। जयपुर में एक बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने रायपुर सत्र के दौरान इसी बारे में बात की थी और जाति जनगणना उसी आधार पर की जाएगी। गहलोत ने कहा कि जनगणना के नतीजों से सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नीति बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में जाति जनगणना की व्यवस्था बनाई थी और उसी के आधार पर हम यहां भी यह काम करेंगे। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातीय जनगणना कराएगी। हम यह अवधारणा लेकर चलेंगे कि जनसंख्या के अनुरूप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। बिहार की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना कराने का दिया जायेगा

हमास के हमले को मोदी ने बताया दुखद, बोले- इस कठिन समय में भारत इजराइल के साथ

हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं : मोदी

नईदिल्ली। गाजा पट्टी में सत्तारूढ़ हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद क्षेत्र में जबरदस्त तनाव है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी है और कहा है कि दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है और हमले आतंकी कार्रवाई कहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। बता दें कि हमास लड़ाकों ने इजराइली सीमा में घुसपैठ करते हुए शनिवार तड़के भारी संख्या में रॉकेट दागे। इजराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने शनिवार को कहा कि हमास के हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।

इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज भी वायरल हैं जिनमें हमास के लड़ाके इजराइली महिलाओं को जबरदस्ती गाजा पट्टी ले जाते हुए देखे गए। सोशल मीडिया पर एक मृत महिला के शव के साथ बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसे इजराइल की सैनिक कहा जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमानों गाजा पट्टी में कई स्थानों पर आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली वायुसेना के ट्वीट के मुताबिक, इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान अब गाजा पट्टी में कई स्थानों पर आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं।

इजराइली मीडिया के मुताबिक, दक्षिणी इजराइल में कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजा में फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने संख्या बताए बिना कहा कि कई नागरिक घायल हैं। इजराइली सेना ने बताया कि उसके सैनिक कम से कम सात जगहों से घुसपैठ करने वाले हमास लड़ाकों के साथ लड़ रहे हैं। नौसेना ने कहा कि हमास लड़ाकों ने हवाई और समुद्री रास्तों से घुसपैठ को अंजाम दिया है। हमास की सैन्य शाखा के एक नेता का कहना है कि सशस्त्र समूह ने इजराइल के खिलाफ एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है। एक सार्वजनिक बयान

में, मोहम्मद दीफ ने कहा कि ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म शुरू करते हुए शनिवार तड़के इजराइल में 5,000 रॉकेट दागे गए। हमास के सैन्य नेता ने सभी फलस्तीनियों से इजराइल का मुकाबला करने का आग्रह करते हुए कहा कि हमने यह कहने का निर्णय लिया है कि अब बहुत हो गया।

लाल किले पर की गई घोषणाओं को लेकर प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान की गई विभिन्न घोषणाओं के कार्यान्वयन की तैयारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रधान मंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पीएम मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्ग को घर के स्वामित्व के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने घरों के लिए सौर ऊर्जा का प्रावधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनके प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा बैठक में शामिल होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में से थे। उन्होंने इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालने के लिए एक प्रस्तुति दी। पीएमओ ने कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधान मंत्री ने गरीबों और मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। इस घोषणा के अनुरूप, प्रधान मंत्री ने इस घोषणा को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की। अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधान मंत्री ने घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना को क्रियान्वित करने की तैयारियों की समीक्षा की।

70 साल में कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया : ज्योतिरादित्य

भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनावी समर के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जबरदस्त तरीके से जारी है। एक ओर भाजपा है तो दूसरी ओर कांग्रेस है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा अपने 70 साल के शासन में कांग्रेस ने देश के पिछले वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का भी विरोध किया था। दरअसल, वर्तमान में जाति आधारित जनगणना की मांग जबरदस्त तरीके से जारी है। कांग्रेस 2024 चुनाव को लेकर इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह भी ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार बनी तो जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी कहा था कि जितनी आबादी उतना हक होना चाहिए। इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की यह प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान (पिछड़े वर्गों पर) एक आयोग की रिपोर्ट पेश की गई, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जब वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया, तो कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। सिंधिया ने कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पिछड़े वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल 60 प्रतिशत सदस्य इन्हीं समुदायों से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाएगी।

कांग्रेस 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी

छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों ने नाम पर होगा मंथन

नईदिल्ली। कांग्रेस राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए 13 अक्टूबर (शुक्रवार) को छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक करेगी। पार्टी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि सीईसी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होगी क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठकें यहां हो चुकी हैं। 4 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सदस्य बनाकर 16 सदस्यीय सीईसी का गठन किया था। सीईसी में अंबिका सोनी, मधुसूदन मिस्त्री, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, एन उत्तम कुमार रेड्डी, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, केजे जियोग्रे, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, अमी याजनिक, पीएल पुनिया, ओंकार मरकाम और केसी वेणुगोपाल भी इसके सदस्य हैं।

कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है और खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। तीनों नेता पहले ही चुनावी राज्य में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित कर चुके हैं। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आदिवासी बहुल राज्य में कई जन-समर्थक योजनाएं शुरू की हैं और उसे लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद है। इस बीच, भाजपा भी चुनाव के लिए कमर कस रही है और उसने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज शाम उनके निवास कार्यालय में

मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ के वृक्ष बहुतायत में पाये जाते हैं।

अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर प्रहार

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और शहरी रोजगार योजना जैसे कई बड़े फैसले किए हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताना चाहिए कि इन्हें केंद्र सरकार अपने यहां कब लागू करेगी। अशोक अशोक गहलोत ने दोहराया कि उनकी सरकार बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत सर्वेक्षण करवाएगी और यह भी एक बड़ा फैसला है। पीएम मोदी ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा में कहा था कि राज्य में सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जनहित की किसी योजना को बंद नहीं करेगी और यह मोदी की गारंटी'' है। इस बारे में पूछे जाने पर अशोक गहलोत ने जयपुर में मीडिया से कहा, इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया है कि हमारी योजनाएं शानदार हैं। वह चिंता नहीं करें, हमने योजनाएं अच्छे ढंग से लागू की हैं। वह तो यह बताएं कि केंद्र में 25 लाख रुपये के बीमा की घोषणा कब करेंगे? बताएं ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) लागू कब करेंगे? बताएं शहरी रोजगार योजना कब शुरू करेंगे?''

खेल
प्रमुख समाचार

एशियाई खेलों में 72 साल बाद भारत ने लगाया मेडल का शतक

हांगझोउ। हांगझोउ में खेले जा रहे एशियाई खेलों 2023 में भारत ने इतिहास रच डाला है और मेडल का सेंचुरी लग दिया है। भारत के खाते में अबतक 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 कांस्य की मदद से कुल 100 मेडल हो चुके हैं। एशियाई खेलों में भारत का यह अबतक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। इधर पदक का शतक लगाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है।

भारतीय दल ने एशियाई खेलों में सौ पदक पूरे कर लिये जब महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपै को शनिवार को रोमांचक फाइनल में 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला कबड्डी टीम का यह तीसरा खिताब है। पिछली बार जकार्ता में उसने रजत पदक जीता था। उसकी खिताबी जीत के साथ ही भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में पदकों का तिहरा अंक छुआ। फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपै ने बेहद कड़ी चुनौती दी लेकिन भारत ने एक अंक से बाजी मारी। हाफटाइम तक भारत के पास पांच अंक की बढ़त थी। पूजा ने भारत के लिये कई अंक जुटाये। भारत की अनुभवी कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई जबकि अदिति स्वामी को कांस्य पदक मिला और इसके साथ ही भारतीय तीरंदाजों ने इन एशियाई खेलों में रिकॉर्ड नौ पदक अपनी झोली में डाल लिये। इससे पहले भारत ने इंचियोन में 2014 में हुए खेलों में तीन पदक जीते थे। मौजूदा विश्व चैम्पियन अदिति स्वामी ने कांस्य पदक के एकतरफा प्लेआफ मुकाबले में इंडोनेशिया की रातिह जिलिजाती एफ को हराया। बर्लिन में दो महीने पहले विश्व चैम्पियनशिप खिताब जीतने वाली 17 वर्ष की अदिति ने 146-140 से जीत दर्ज की। बाद में ज्योति ने दक्षिण कोरिया की सो चाएवोन को 149-145 से हराकर तीसरा स्वर्ण जीता।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश घटकर 79.34 करोड़ डॉलर पर

नईदिल्ली। कार्यालय परिसंपत्तियों में रफ्तार धीमी होने के कारण चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 21 प्रतिशत घटकर 79.34 करोड़ डॉलर रह गया। कोलियर्स इंडिया ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 100.21 करोड़ डॉलर था। रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया ने शनिवार को एक रिपोर्ट में आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार, कार्यालय परिसंपत्तियों में जुलाई-सितंबर के दौरान निवेश में 89 प्रतिशत की भारी गिरावट आई और यह 7.91 करोड़ डॉलर रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 69.43 करोड़ डॉलर था। कोलियर्स इंडिया ने बताया कि जुलाई-सितंबर अवधि के दौरान मिश्रित उपयोग वाली परिसंपत्तियों में भी धन प्रवाह 73 प्रतिशत घटकर 2.72 करोड़ डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 10.08 करोड़ डॉलर था।

मिलेट्स से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी 8% की जगह 5%

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हुई। यह बैठक सुषमा स्वराज भवन में चल रही है, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बाजरा के आटे (मिलेट्स के आटे) पर जीएसटी को मौजूदा 18% जीएसटी से घटाकर 5% करने का फैसला किया है। माल व सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को शीरे पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का किया है। जीएसटी परिषद के सदस्य और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक उपयोग के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर माल व सेवा कर (जीएसटी) लगता रहेगा।

अब बैंकों से नहीं बदल सकेंगे 2000 के नोट

नईदिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा दो हजार रुपये के नोट बंद किया जा चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी दो हजार रुपये का नोट है तो इसे बदलने और खाते में जमा करने का 7 अक्टूबर को अंतिम मौका था। दो हजार रुपये के नोट अब 7 अक्टूबर के बाद बैंकों में बदले नहीं जाएंगे। दो हजार रुपये के नोटों को बैंकों में जवाब भी नहीं किया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध होगी। वही जो लोग नोट बदलने इन क्षेत्रीय कार्यालय में नहीं जा पाएंगे वह डाक के जरिए नोट बदल सकेंगे। अब भी काफी मात्रा में दो हजार रुपये के नोट बाजार में चल रहे है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कुछ समय पूर्व चलन से वापस लिए गए 2000 के नोट बैंकों में वापस आए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 87% नोट जनता ने बैंकों में जमा करवा दिए हैं। वही शेष प्रतिशत को अन्य मूल्य के नोटों से बदल गया है।

असुरक्षित कर्ज में वृद्धि पर आरबीआई ने जताई चिंता

नई दिल्ली। खुदरा कर्ज खासकर पर्सनल लोन और अन्य असुरक्षित कर्ज में बेतहाशा वृद्धि पर आरबीआई ने चिंता जताई है। दास ने कहा कि बिना गारंटी वाले कर्ज वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हैं। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि हालात पर नियंत्रण के लिए बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और फिनटेक आंतरिक निगरानी तंत्र मजबूत करें। साथ ही, मजबूत जोखिम प्रबंधन भी लागू करें। केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर जे स्वामीनाथन ने कहा, गवर्नर की इस संबंध में टिप्पणियां सिर्फ एक सलाह है। स्वामीनाथन ने चेतावनी दी कि बैंक व एनबीएफसी पर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आरबीआई खुद इसकी जांच करेगा। पिछले दो वर्षों में कुल बैंकिंग कर्ज 12-14 फीसदी बढ़े हैं। इस दौरान असुरक्षित खुदरा कर्ज में 23 फीसदी वृद्धि हुई है, जो नियामक के लिए चिंता की बात है।

व्यापार पर विवाद भारी तो शांति का संदेश जारी

अनिल तिवारी

भारत आतंकवाद और अलगाववाद का मुखर विरोधी रहा है। दुनिया के हर मंच पर भारत ने ऐसी ताकतों का एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान किया है। कनाडा भारत का अंतरंग कारोबारी देश रहा है। ऐसे में भारत कनाडा को एक दूसरा पाकिस्तान क्यों होने देना चाहेगा, जहां आईएसआई के इशारे पर खालिस्तानी अलगाववादी बेधड़क पाले पोसे जाएं। इसलिए भारत ने कनाडा से बार-बार खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

भारत की मांग पर कोई ठोस कार्यवाही करने के बजाय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने न सिर्फ भारत पर बिना किसी सबूत के खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया बल्कि अधिक उतावलेपन में कनाडा सरकार ने एक भारतीय राजनयिक को निकालने की कार्रवाई भी कर दी। भारत ने कड़ा रूख अपनाते हुए 10 अक्टूबर तक कनाडा के 40 राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया है।

भारत के आईना दिखाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कस-बल ढीले पड़ने लगे हैं। दबाव बढ़ता देख उनकी बोली भी बदल गई। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ करीबी संबंधों को लेकर कनाडा बहुत गंभीर है। इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री मैलानी जोली ने भारत सरकार के साथ संपर्क साधा है और कहा है कि कनाडा नई दिल्ली के साथ रचनात्मक बातचीत करके राजनयिक बातचीत बढ़ाना चाहता है। दोनों देश अहम भू राजनीतिक भागीदार हैं। ऐसे में जरूरी है कि दोनों देश मिलकर काम करें ताकि दोनों देशों के आर्थिक संबंध पटरी पर बने रहे।

मैलानी की कूटनीतिक शांति विराम की घोषणा उनके गहरे आर्थिक हितों से जुड़ी है।

भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में आई तल्खी के कारण दोनों देशों के कारोबार-व्यापार के नुकसान का अंदेशा है। हालांकि भारत के कड़े रुख और अपने घरेलू अर्थशास्त्र की जरूरतों को देखते हुए कनाडा अब नरमी का संकेत दे रहा है, लेकिन ईपीटीए (अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट) समझौता वार्ता के रुक जाने से दोनों देशों के बीच 17 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का सौदा खटाई में पड़ गया है। यह वार्ता इसी महीने प्रस्तावित थी जिसे दोनों देशों ने तनातनी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है।

भारत और कनाडा के बीच अच्छा खासा व्यापार होता रहा है। कनाडा की कंपनियों ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, तो भारतीय कंपनियां भी कनाडा की अर्थव्यवस्था में लगातार योगदान देती आई हैं। कनाडा पेंशन फंड का भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश है। उसने फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो से लेकर ब्यूटी ब्रांड नायका तक में इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि विवाद के चलते कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड बिकवाली कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि भारत और उसकी कंपनियां कनाडा के बाजार से अपने हाथ खींचने लगती तो उसके लिए भारी मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों का भारी योगदान है। करीब 30 भारतीय कंपनियों ने कनाडा में 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया हुआ है। यह कंपनियां हजारों लोगों को रोजगार दे रही हैं, इसलिए कनाडा चाहकर भी भारत में निवेश किया पैसा फिलहाल नहीं निकाल सकता। इसके अलावा कनाडा की कंपनियों को भारत में अच्छा रिटर्न मिलता है। इसलिए यहां अपना निवेश कायम रखना उसके लिए जरूरी है। वहीं दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023 में भारत ने कनाडा को 4.11 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था जबकि इसका आयात 4.7 अरब डॉलर का था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दोनों देशों के बीच सात अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 9 अरब डालर तक पहुंच गया। कनाडा भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार नहीं है किंतु उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत पर निर्भर है। कनाडा में बसे भारतीय नागरिकों और छात्रों की वहां की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका है।

कही-सुनी

रवि भोई

कांग्रेस के 15 विधायकों की कट सकती है टिकट

माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार कई नए चेहरे को मैदान में उतारेगी। इसके लिए वह 12 से 15 वर्तमान विधायकों की टिकट काट सकती है। कहा जा रहा है कि पहली बार के विधायकों की टिकट ज्यादा कटेगी। ख़राब परफार्मेंस वाले कुछ पुराने विधायकों को भी पार्टी चुनाव मैदान से बाहर कर सकती है। कहा जा रहा है कि ईडी के निशाने पर आए विधायकों को भी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। इसके अलावा विवादों में रहने वाले या किसी न किसी कारण से दागदार हो चुके विधायकों का भी पत्ता साफ़ माना जा रहा है। इस बार कांग्रेस कुछ प्रोफेशनल्स को मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस का लक्ष्य हर हाल में सत्ता में वापसी है।

वायरल सूची से उलट होगी भाजपा की दूसरी लिस्ट

भाजपा प्रत्याशियों की वायरल सूची को लेकर बवाल मचने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि असल लिस्ट उसके उलट होगी। कई नए चेहरों के साथ जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के टेस्ट के लिए भाजपा के कुछ नेताओं ने जानबूझकर गलत लिस्ट को वायरल कर दिया। इससे कई प्रत्याशियों के बारे में पार्टी हाईकमान को जानकारी मिल गई। भाजपा की दूसरी लिस्ट वायरल होने के बाद अब तक धरसींवा, साजा, आरंग, बसना,रायपुर उत्तर और कई विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर चुके हैं। पहली लिस्ट में घोषित कुछ नाम को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पहली लिस्ट के कुछ नामों में उलटफेर होने की संभावना है।

भाजपा की सीट बिकने की चर्चा

चर्चा है कि महासमुंद जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में से एक को भाजपा नेताओं ने बेच दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट के बिकने की खबर फैली थी।2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी तीसरे स्थान पर आया था। तब पार्टी के एक दिग्गज नेता पर सीट बेचने का आरोप लगा था। इस बार आरएसएस से जुड़े दो नेताओं पर साठगांठ का आरोप लग रहा है। भाजपा ने पहली सूची में दो सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दो प्रत्याशियों के नाम वायरल लिस्ट में है। जिले के चारों सीटों के प्रत्याशियों को लेकर बवाल मचा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घोषित और संभावित प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

बड़बोलापन ले डूबा कांग्रेसी दावेदार को

कहते हैं रायपुर के एक विधानसभा के लिए कांग्रेस की टिकट के दावेदार को बड़बोलापन और प्रचार भारी पड़ गया। चर्चा है कि कांग्रेस की टिकट के दावेदारों में अव्वल चल रहे इस नेता को अपना प्रचार भारी पड़ गया। खबर चल रही है कि इस नेता ने टिकट के लिए कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी को मोटी रकम दी है। इस खबर के फैलने के बाद नेता का ग्राफ गिर गया और दुश्मनों ने भी गड्ढा खोद दिया। कहा जा रहा है कि लेनदेन की खबर के बाद नेताजी का पत्ता साफ़ हो गया है और उस सीट से अब तीसरे व्यक्ति का नाम दौड़ने लगा है।

निहारिका बारिक से गुस्से में सरकार

चर्चा है कि 1997 बैच की आईएएस निहारिका बारिक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुस्सा तीन साल बाद भी शांत नहीं हुआ है।

निहारिका बारिक भूपेश बघेल की सरकार में स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं। इसके बाद वे दो साल के लिए चाइल्ड केयर लीव में चली गईं। बाद में एक साल और अवकाश बढ़ा लिया था। वे पिछले दिनों अवकाश से लौटीं , तो सरकार ने उन्हें मुख्य धारा में पदस्थ करने की जगह मंत्रालय से बाहर की पोस्टिंग दे दी। निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव स्तर की अधिकारी हैं और उन्हें महानिदेशक ,राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के पद पर पदस्थ किया गया है। राज्य में अभी मनोज पिंगुआ के अलावा और कोई प्रमुख सचिव नहीं है, फिर भी निहारिका बारिक को मंत्रालय में कोई विभाग न देना सरकार की नाराजगी साफ़ दिखती है। खबर है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीआर में निहारिका बारिक की रेटिंग भी कम की थी।

पुलिस अफसरों पर ईडी की नजर

कहते हैं महादेव ऐप मामले में ईडी छत्तीसगढ़ के कुछ पुलिस अफसरों पर सतत नजर बनाए हुए है। चर्चा है कि ईडी के करीब तीन दर्जन अधिकारी-कर्मचारी पुलिस अफसरों पर नजर बनाए हुए हैं। खबर है कि ईडी का यह स्टाफ अलग-अलग राज्यों से छत्तीसगढ़ आया हुआ है। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों ईडी के कुछ लोगों ने कुछ अफसरों के आफिस और बंगले की रैकी भी की। महादेव ऐप मामले में बॉलीवुड के कुछ कलाकारों को समन जारी होने के बाद माना जा रहा है कि राज्य के कुछ पुलिस अफसरों को भी ईडी चपेट में ले सकती है।

विधानसभा चुनाव की घोषणा नौ अक्टूबर को संभव

चर्चा है कि भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा सोमवार नौ अक्टूबर को कर सकती है।

चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान कराए जाएंगे। दूसरे चरण में मैदानी इलाकों में चुनाव होगा। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों चरणों की वोटिंग नवंबर में दीवाली के बाद ही होगी।

नवरात्रि में कांग्रेस-भाजपा की लिस्ट

कहा जा रहा है कि नवरात्रि में ही कांग्रेस-भाजपा की लिस्ट आएगी। तब तक चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। माना जा रहा है कि दोनों दल दो-तीन चरणों में प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट अगस्त में ही जारी कर दी थी, लेकिन दूसरी लिस्ट लटकी हुई है। लोगों को भाजपा और कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। आप, बसपा और दूसरे दल भी लिस्ट जारी कर रहे हैं , उसमें लोगों की खास दिलचस्पी नहीं है , इससे लगता है कि राज्य में मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस में ही रहेगा।

दुश्मन हुए दोस्त

कहते हैं न समय दुश्मनों को दोस्त बना देता है, ऐसा ही कुछ नजारा आजकल राजनीति में देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि रायपुर के एक विधानसभा से टिकट के दावेदार भाजपा नेता कुछ दिन पहले तक एक-दूसरे के जानी दुश्मन थे। वायरल सूची आने के बाद दावेदार दोस्त बन गए हैं और वह नहीं, हममें से किसी एक को उम्मीदवार बनाने का नारा लगाने लगे हैं। अब देखते हैं यह दोस्ती कब तक टिके रहती है।

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

संविधान को सर्वोच्च मानते हुए इसकी रक्षा करना सभी की जिम्मेदारीः सीएम बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित अम्बेडकर चौक में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की नवीन प्रतिमा स्थापना हेतु आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए । इस अवसर पर विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा एवँ जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे । मुख्यमंत्री बघेल ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि अंबेडकर जयंती के दिन यह बात सामने आयी कि बाबा साहब की वर्तमान मूर्ति बहुत पुरानी और खण्डित हो गई है इसलिए इसके स्थान पर नई

मूर्ति की स्थापना की जाये। यह जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई, निगम ने इसके लिए टेंडर निकाला, प्रक्रिया पूर्ण की और मूर्ति भी अब निर्माणाधीन है । आज मूर्ति स्थापना कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है, इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई एवँ शुभकामनाएं देता हूं । मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर चलकर हम समाज और देश को आगे ले जा सकते हैं । उन्होंने हमें जो संविधान दिया है वह सभी देशवासियों के लिए सबसे बड़ी ताकत है । इसी संविधान के तहत हम सभी को अधिकार और बहुत सी स्वतंत्रताएं मिली हैं । अब यदि संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा तो यह देशवासियों को कमजोर करने का प्रयास होगा, जिससे देश भी कमजोर होगा । संविधान को सर्वोच्च मानते हुए संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि यही संविधान हम सभी को अधिकार सम्पन्न बनाता है ।

दिल्ली से जो भी कांग्रेसी आता है, वह भू-पे का गुण गाता हैः रंजना

रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें बोलने के लिए जो रटाया गया है, वह बोलना उनकी विवशता है। वे एआईसीसी की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं तो मीडिया में छाई छत्तीसगढ़ की असल तस्वीर भी देख लें। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की काली करतूतों पर परदा डालने की कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। दिल्ली से जो भी कांग्रेसी आता है, वह भूपेश बघेल के मायाजाल में फंस जाता है। हर किसी की आंख पर भू-पे की पट्टी बंध जाती है। जब लड़ने का नारा देने वाली कांग्रेसी लड़की छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए लड़ने की बजाय भूपेश राग अलापती हो तब राधिका खेरा से छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां भला क्या उम्मीद कर सकती हैं। दिल्ली से आने वाले सारे कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की भाषा बोलने बाध्य हैं। सब के सब भू-पे के वश में हैं। भूपेश के झूठ को दोहराना ही इनके छत्तीसगढ़ आने का मकसद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को छत्तीसगढ़ में यही काम सौंपा गया है।

किसान नेता योगेश तिवारी हजारों साथियों सहित भाजपा में शामिल

रायपुर। राजधानी के रावणभाटा में आयोजित भाजपा प्रवेश विशाल उत्सव में किसान नेता योगेश तिवारी ने हजारों साथियों समेत आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर करीब 10 हजार लोग मौजूद रहे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं छत्तीसगढ़ चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोरोना महामारी से दुनिया परेशान थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को वैक्सीन दिया। छत्तीसगढ़ को वैक्सीन दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कहती थी कि यह वैक्सीन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 लाख आवास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा भेजने के लिए

तैयार थी लेकिन प्रदेश की सरकार को लगता है कि यहां लोगों को आवास मिल जाएगा तो वे लोग मोदी को वोट कर देंगे। कांग्रेस हमेशा वोट की राजनीति करती है लेकिन वोट की राजनीति के चलते उन्हें गरीबों के प्रधानमंत्री आवास नहीं छीनना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना चालू की लेकिन जल जीवन मिशन भी छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। लेकिन इन योजनाओं का संचालन भी प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं होने दे रही। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार रोकने का काम करती है। छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने वाली केंद्रीय योजनाओं के लाभ से प्रदेश की कांग्रेस सरकार उन्हें वंचित करने का काम कर रही है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

धान खरीदी में मोदी सरकार केवल अड़ंगे लगाती है : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी के लिये केन्द्र सरकार एक रू. भी नहीं देती है। भाजपा लगातार झूठ बोलकर जबरिया श्रेय लेने की कोशिश में है मोदी और साव कितना भी झूठ बोल ले इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली मोदी सरकार धान खरीदी में सिर्फ अडंगे बाजी ही लगाती है कोई सहयोग नहीं करती है। हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में धान कांग्रेस सरकार अपने खुद के

दम पर खरीदती है, धान खरीदने में केन्द्र सरकार का एक पैसे का भी योगदान नहीं है। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है इसके लिये मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है तथा इस ऋण के लिये बैक गारंटी राज्य सरकार देती है तथा धान खरीदी में जो घाटा होता है उसको भी राज्य सरकार वहन करती है पिछले वर्ष मार्कफेड ने लगभग 35000 करोड़ का ऋण धान खरीदी के लिये लिया था। मोदी सरकार तो घोषित समर्थन मूल्य से 1 रूपये भी ज्यादा कीमत देने पर राज्य सरकार को धमकाती है की वह राज्य से केन्द्रीय योजनओं के लिये लगने वाला चावल नही खरीदेंगे। अकेली छत्तीसगढ़ सरकार है जो अपने धान उत्पादक किसानों को देश में सबसे ज्यादा कीमत देती है। छत्तीसगढ़ के किसानों को पिछले वर्ष धान की कीमत 2640 मिली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जैसे राज्यों में तो किसानों को धान का मूल्य 1100 रूपये मिलता है।

मोदी सरकार जिन गरीबों का घर छीना उसे भूपेश सरकार बनवा रहीः ठाकुर

रायपुर। भाजपा के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद भाजपा अपने घर में लगी आग बुझाने के बजाये दूसरों के घरों में तांक झांक कर रही है। कांग्रेस में टिकट कब आयेगा, प्रत्याशी कौन होगा ये सब कार्यकर्ता और नेता मिल बैठकर करते है। लेकिन भाजपा में तो न दावेदारों

को महत्व मिल रहा है न कार्यकर्ताओ से पूछा गया है सिर्फ भाजपा के केंद्रीय नेताओ की तानाशाही चल रही है जिसका ही परिणाम है। भाजपा की 21 प्रत्याशी की पहली सूची के बाद 21 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता घोषित प्रत्याशी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब भाजपा के एक वायरल सूची जारी आने के बाद तो टिकट के दावेदार उनके समर्थक कालिख लेकर भाजपा के बड़े नेताओं को दौड़ा रहे है। दिल्ली से रायपुर आकर रात में बैठक करने वाले भाजपा के बडे नेता अब दावेदारों और कार्यकर्ताओं के गुस्सा को देखते हुये छत्तीसगढ़ नही आ रहे है बल्कि जी हुजूरी करने वाले भाजपा के चंद स्थानीय नेताओं को दिल्ली बुलाकर लीपा पोती करने में लगे है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश के गरीबो को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने में असफल मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा करने राज्य सरकार पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है।

सत्ता की भूख में रमन बदनाम कर रहे : शुक्ला

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा पीएससी के मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सत्ता की भूख में रमन सिंह पीएससी जैसी विश्वसनीय संस्था को बदनाम कर रहे है। राज्य लोक सेवा जैसी संस्था के नाम पर रमन सिंह और भाजपा स्तरहीन राजनीति कर रहे है। पीएससी में गड़बड़ी के कोई भी तथ्य एवं साक्ष्य

रमन सिंह के पास नहीं है सिर्फ सरकार को बदनाम करने कुचेस्टा में झूठे आरोप लगा रहे है। रमन सिंह में साहस हो तो वे नान घोटाले, चिटफंड घोटाले और पनामा पेपर घोटाले की जांच के लिये भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते भाजपा नेता चंद्रशेखर साहू जो उस समय पीएससी के मेंबर भी थे ने प्रेस कांफ्रेस लेकर पीएससी में गड़बड़ी के आरोप लगाया था तब रमन सिंह ने उसकी जांच भी नहीं करवाया था आज गलत आरोप लगाकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुये हों।किसी परीक्षार्थी ने लेनदेन की प्रमाणिक शिकायत किया हो। किसी कोचिंग संस्थान के पूर्व अनुमानित प्रश्न पत्रों के सेट से पीएससी के प्रश्न पत्र हू-बहू मिल रहे थे। मेरिट में चयनित अभ्यार्थियों के इन्टरव्यू के नंबर लिखित परीक्षा के अंको में बहुत ज्यादा असमानता नजर आ रही थी।

महंगाई पर मौन क्यों है भाजपा नेत्रियांः शिल्पा देवांगन

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन ने कहा कि महंगाई पर भाजपा की नेत्रियां मौन क्यों है? महंगाई के खिलाफ गृहणियों की आवाज उठाने से क्यों डर रही है? 2014 के पहले महंगाई पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली, आलू-प्याज की माला पहनने वाली नेत्रियां अब गायब है। 100 दिनों में महंगाई कम कर जनता को राहत देने की गारंटी देकर सत्ता में आने वाले मोदी सरकार की मुनाफाखोरी के नीति के चलते जनता आज महंगाई से परेशान हैं मोदी

सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां संगठित होकर जनता से पेट्रोल डीजल में मुनाफा कमा रही है। जनता महंगाई से बेहाल है। मोदी सरकार खुद के मुनाफा और पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए क्रूड ऑयल की कीमत में 35 प्रतिशत की कमी का फायदा जनता को नहीं दे रही है।बीते 9 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल में भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी लगाकर 30 लाख करोड़ रुपए गरीब जनता की जेब से निकाल लिया है और अब पेट्रोलियम कंपनियों को संरक्षण देकर उनके फायदा के लिए काम कर रही है। गरीब जनता महंगाई से कहरा रही है उनकी पीड़ा को केंद्र की सरकार अनसुना कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन ने मोदी सरकार से पूछा जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल के दाम में 35 प्रतिशत तक की गिरावट आई है फिर देश के भीतर पेट्रोल डीजल की दरों में 35 प्रतिशत की कमी क्यों नहीं की गई? पेट्रोल डीजल के दामों में 35 प्रतिशत की कमी की जाती है।

हजारों ट्रेनें रद्द करने पर मोदी सरकार श्वेत पत्र जारी करेः वर्मा

रायपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव के बयान पर पलट बार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अरूण साव यह जान ले कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से वसूलती ज्यादा है और देती कम है। बिलासपुर रेलवे जोन, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, वहां से केंद्र की मोदी सरकार हर साल 20 से 22 हजार करोड़ वसूलती हैं। पिछले 5 साल में

लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि केंद्र की मोदी सरकार ने केवल बिलासपुर रेलवे जोन से कमाया है लेकिन जब देने की बारी आती है तो मोदी सरकार ने हमेशा ही छत्तीसगढ़ की उपेक्षा ही की है। नई ट्रेन तो छोड़िए पिछले 3 साल में छत्तीसगढ से गुजरने वाली 68 हजार ट्रेन रद्द की गई। मोदी राज में कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा जब छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली दर्जनों यात्री ट्रेनें रद्द न की गयी हो। पिछले साढ़े 4 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से पेट्रोलियम पदार्थो में सेंट्रल एक्साइज, आयकर, केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय करों में सेस बिलासपुर जोन से रेलवे की कमाई, कोल खनन, आयरनओर, बॉक्साइट टीन खनन सहित लगभग 4 लाख 61 हजार 908 करोड़ छत्तीसगढ़ से वसूला है और इस दौरान छत्तीसगढ़ को केंद्र से 1 लाख 92 हजार करोड़ मिलना था जिसमें भी केवल 1 लाख 37 हजार 190 करोड़ 76 लाख ही मिला है।

छत्तीसगढ़ के युवा अभ्यर्थियों के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

सीजीपीएससी में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करवाने किया आग्रह

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है, संबंधित दस्तावेजों को संलग्न कर उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा लोक सेवा आयोग (छ्त्तक्स्ष्ट) में प्रतिवर्ष क़रीब डेढ़ लाख युवा प्रतिभागी शामिल होते हैं, इस परीक्षा में प्रदेश के प्रमुख पदों पर भर्ती की जाती है जिसमें अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों के अभ्यर्थी भाग लेते हैं। इस परीक्षा के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता को समाप्त कर एक बड़े घोटाले से भाई-भतिजावाद शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम में शीर्ष 18 नाम, कांग्रेस नेताओं, सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष तथा बड़े अधिकारियों के बच्चों और रिश्तेदारों के हैं तथा उच्च पदों पर उनका चयन हुआ है। इसके विरुद्ध युवाओं में निराशा और आक्रोश को देखते हुए पूर्व गृह मंत्री एवं वर्तमान में रामपुर विधायक श्री ननकीराम कंवर जी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगायी और चयनित कुल 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा, चूंकि उनमें से 5 की नियुक्ति हो चुकी थी अत: वर्तमान में कुल 13 की नियुक्ति पर रोक लगी है।इसके साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में भी की गई धांधली उजागर हुई है जिसमें किसी अभ्यर्थी को बिना उत्तर लिखे अंक देना, किसी को कम अंक आने पर भी चयनित तथा किसी को अधिक अंक आने पर भी बाहर करना आदि शामिल है।

प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार की जाँच पर भरोसा नहीं है और उनका आरोप है कि राज्य सरकार के संरक्षण में पैसे लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं, बड़े अधिकारीयों तथा सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष के बच्चों और रिश्तेदारों का चयन किया गया है, युवाओं का राज्य सरकार पर विश्वास न होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यह झूठ कहकर इसकी जाँच नहीं करवाई कि युवाओं ने इसकी शिकायत नहीं की है जबकि प्रदेश के युवाओं ने इसकी लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से की थी जिसकी प्रति संलग्न है।

कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गयी हैः संजय

रायपुर। भाजपा के सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गयी है! न बीरबल की खिचड़ी पक रही है और न कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है, जो बताता है कि कांग्रेस के घर में गुटबाजी अपने चरम पर है। इसलिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री में तालमेल नहीं दिख रहा है। देश के राजनीतिक इतिहास में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पहली ऐसी सरकार है, जो अपने

काम, प्रभाव और उपलब्धियों के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकार पर दोषारोपण करके चुनाव के मैदान में जा रही है।

जो सरकार होती है, उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि उसने जो काम किया अपने शासनकाल में किया है, वह जनता को बताए और फिर से जनादेश मांगे। भाजपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने भी यही किया था। आज प्रदेश में भाजपा विपक्ष में है और उसका यह अधिकार और दायित्व है कि वह सरकार की कमियों पर नजर रखे, लेकिन मौजूदा प्रदेश की भूपेश सरकार जिस तरह नकारात्मक बिंदुओं पर चुनाव लड़ने जा रही है, उससे यह आईने की तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस की इस सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि या ऐसा कोई प्रभावी काम नहीं है।6 माह पहले तक कांग्रेस की जो सरकार अपनी तथाकथित उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटती अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही थी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.